लखनऊ

रविवार, 23 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 | अंक: 354

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में रोशनी लाई जा सकती है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ पहली बैठक

संगठन और पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल एजेंडे में शामिल

युवा वोटरों को साधने पर फोकस: जेन-ज़ी आउटरीच के लिए खास टीम, भाजपा की नई टीम की पहली बैठक में क्या- क्या हुआ

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने देश भर के युवाओं के साथ जुड़ाव को मजबूत करने के मकसद से अपने आने वाले 'जेन-जी आउटरीच प्रोग्राम' को आगे बढ़ाने के लिए एक खास टीम बनाई है।

शनिवार को पार्टी के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया, 'इस आउटरीच पहल के लिए बनाई गई टीम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े, गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी, छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी और कई अन्य नेताओं को शामिल किया गया है।'

उम्मीद है कि भाजपा जल्द ही जेन जी के साथ यह आउटरीच प्रोग्राम शुरू करेगी। यह युवा पीढ़ी के साथ ज्यादा सीधा और लगातार संवाद कायम करने की पार्टी की कोशिशों का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का मकसद 'जेन जी' की उम्मीदों, चिंताओं और अपेक्षाओं को समझना है। इसके साथ ही, यह युवाओं को भाजपा नेताओं से सीधे जुड़ने और उनसे जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने का मंच भी देगा।

पार्टी इस पहल का इस्तेमाल युवा वोटरों के साथ अपना जुड़ाव मजबूत करने और बातचीत, चर्चा व अन्य गतिविधियों के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भी करेगी। टीम में अलग-अलग संगठनात्मक और राजनीतिक बैकग्राउंड वाले नेताओं को शामिल करना यह दिखाता है कि भाजपा नई पीढ़ी तक पहुंचने के साथ-साथ संगठनात्मक अनुभव और युवा नेतृत्व को एक साथ लाने पर ध्यान दे रही है।

नई टीम की पहली बैठक हुई

'जेन-जी' आउटरीच प्रोग्राम के शेड्यूल, फॉर्मेट और जगहों के बारे में और जानकारी जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नई बनी राष्ट्रीय टीम की पहली परिचय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक बीजेपी पदाधिकारियों के तौर पर उनकी नई पारी की औपचारिक शुरुआत होगी।

बैठक में क्या- क्या हुआ?

इस बैठक में भाजपा के देशव्यापी 'मोदी@25' अभियान को लेकर चर्चा हुई ह। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया है। इसके साथ ही हर पदाधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारियों के क्षेत्रों पर चर्चा हुई। वहीं, बैठक में अगले साल सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को और 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों और संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई।

पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले सियासी टकराव, एनएसयूआई–एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प

पुणे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में पुणे में होने वाले 'छात्रों की गूंजÓ कार्यक्रम से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है। शिवाजीनगर स्थित सीईओपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प की घटना सामने आई है।

घटना के बाद दोनों छात्र संगठनों ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। झड़प के चलते विश्वविद्यालय परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की तैयारियों के बीच एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों गुट आमने-सामने आ गए और मामला झड़प तक पहुंच गया। हालांकि, विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और झड़प की शुरुआत किसने की, इसे लेकर अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटना पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि पुणे में शिक्षा की गुणवत्ता, सुविधाओं और छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारी असंतोष है। सपकाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को छात्रों का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिससे विरोधी असहज हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को बाधित करने और माहौल खराब करने के लिए भाड़े के लोगों के जरिए स्टंट करने की साजिश रची गई है।

चीनी कम, इथेनॉल ज्यादा खड़गे ने पूछा– ये ' आत्मनिर्भर भारत ' का कौन सा गणित है, मोदी सरकार जवाब दे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 अगस्त को चीनी की बढ़ती कीमतों और चीनी के अपर्याप्त स्टॉक को लेकर भारत सरकार की आलोचना की और सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। X पर एक पोस्ट में, खड़गे ने त्योहारों के मौसम से पहले की स्थिति को लेकर मोदी सरकार से तीन सवाल पूछे। उन्होंने लिखा कि त्योहारों से पहले, मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट चीनी की मिठास में घुल गई है।

उन्होंने पूछा कि भारत, जो दुनिया में चीनी का एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, वहां चीनी का स्टॉक पिछले नौ सालों में सबसे निचले स्तर पर क्यों है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि चीनी के निर्यात पर रोक और दस लाख टन चीनी के बिना ड्यूटी वाले आयात का फ़ैसला कैसे लिया गया। उन्होंने तीन महीनों में चीनी की कीमतों में लगभग 40% की बढ़ोतरी की वजह भी पूछी और त्योहारों से ठीक पहले ग्राहकों पर पड़ने वाले इस बोझ की आलोचना की। इसके अलावा, खड़गे ने सवाल किया कि देश में चीनी की कमी और आयात के बावजूद, इथेनॉल उत्पादन (जिसका इस्तेमाल E20 पेट्रोल ब्लेंडिंग में होता है) के लिए गन्ना और अनाज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली नीति की समीक्षा क्यों नहीं की गई है।

खड़गे ने आगे कहा कि पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गया, अब हम विदेश से चीनी मंगा रहे हैं और दूसरी तरफ, हम पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में कर रहे हैं! इसके जवाब में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 21 अगस्त को कहा कि चीनी की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी - जो 20 जुलाई को 48.18 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई - इथेनॉल के लिए चीनी के इस्तेमाल (डायवर्जन) के कारण नहीं, बल्कि कई अन्य कारणों से हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना गलत है और बताया कि इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी की मात्रा 2022-23 में लगभग 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% हो गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अब इथेनॉल का लगभग तीन-चौथाई उत्पादन अनाज, खासकर मक्के से होता है। सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कई कारण बताए: उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ी हुई मांग, रेड रॉट और टॉप बोरर बीमारी से गन्ने की फसल को हुआ नुकसान, और बहुत ज़्यादा बारिश के कारण खेतों में पानी का जमाव।

4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एफडीसी दवाओं पर रोक, लेबल पर चेतावनी लिखना अनिवार्य

नई दिल्ली, एजेंसी। छोटे बच्चों की सेहत और सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि अब इन दो सामग्रियों वाले किसी भी फॉर्मूलेशन का उत्पादन या बिक्री नहीं की जा सकेगी। साथ ही, कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे इन दवाओं के लेबल पर स्पष्ट चेतावनी लिखें कि इनका इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने इस फैसले के पीछे बच्चों की सुरक्षा को सबसे बड़ा कारण बताया है। दरअसल, यह फैसला एक एक्सपर्ट कमेटी और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन का कॉम्बिनेशन चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस उम्र के बच्चों में इसके दुष्प्रभाव अधिक देखे जा सकते हैं, जबकि इसके सुरक्षित विकल्प बाजार में मौजूद हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को जारी की गई अधिसूचना के जरिए सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ खास एफडीसी पर ही रोक लगाई थी, जिसमें उम्र से जुड़ी चेतावनी शामिल थी। लेकिन ताजा अधिसूचना के साथ सरकार ने इस नियम का दायरा बढ़ा दिया है। अब यह रोक इन दोनों सामग्रियों वाले सभी तरह के फॉर्मूलेशन पर लागू होगी, चाहे वह किसी भी ब्रांड या डोज में हो। नई अधिसूचना के अनुसार, सभी मैन्युफैक्चरर्स को निर्देश दिया गया है कि वे इन फॉर्मूलेशन से जुड़े लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से यह चेतावनी अनिवार्य रूप से लिखें - फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं किया जाना चाहिए।

गोरखा मुद्दे पर ' फाइनल डील ' की तैयारी : शाह की बैठक के बाद MHA ने बनाई कमेटी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गोरखा नेताओं, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य हितधारकों की बैठक के बाद गोरखा मुद्दे के स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में अहम पहल सामने आई है। भाजपा सांसद राजू बिस्टा के अनुसार, गृह मंत्रालय ने मध्यस्थ पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित की है, जो बैठक में बनी सहमति के आधार पर अंतिम समझौते का मसौदा तैयार करेगी। यह पहल 1988 के गोरखा समझौते की वर्षगांठ के दिन हुई बैठक के कारण भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

शाह के उत्तर बंगाल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन दार्जिलिंग की तलहटी में स्थित सुकना के एक होटल में यह अहम बैठक हुई। इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, पहाड़ी इलाकों की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता और क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारक शामिल हुए।

बिस्टा ने कहा कि मध्यस्थ पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय के तहत एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति आज हुए समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देने का काम करेगी।

अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को इस मुद्दे के लिए आधिकारिक सरकारी मध्यस्थ नियुक्त किया था। उनकी भूमिका राजनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने और गोरखा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही

वंदे मातरम पर सियासी घमासान: भाजपा ने कांग्रेस के फैसले को नकारा, कहा- 1937 के इसी फैसले ने रखी विभाजन की नींव

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बार बैठक की। इस बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि पदाधिकारियों की इस बैठक में पहला प्रस्ताव वंदे मातरम के सम्मान को लेकर पारित किया गया। संबित पात्रा ने इस दौरान कांग्रेस के वंदे मातरम के केवल दो छंद गाने के फैसले को लेकर निशाना साधा।

संबित पात्रा ने कहा कि वंदे मातरम के बीज मंत्र के मूल में देश और देशभक्ति है। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से वंदे मातरम को रोकने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ़यह वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है। 15 अगस्त, 2026 को लाल किले से छह श्लोकों वाला संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया। लेकिन 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में एक अशोभनीय घटना घटी।'

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में, जब तिरंगा फहराया जा रहा था, सोनिया गांधी ने दो श्लोकों के बाद वंदे मातरम रोकने का इशारा किया। कांग्रेस इस मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही थी। 19 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक प्रस्ताव आया कि हम वंदे मातरम के केवल दो श्लोक गाएंगे। कांग्रेस वंदे मातरम का विभाजन करना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था।' भाजपा सांसद ने आगे कहा, "1937 में केवल दो छंद गाने का यह फैसला क्यों लिया गया, हम सब जानते हैं। वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में देश में आपातकाल लगा हुआ था। 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में चर्चा होती है। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोकती थी। आज कांग्रेस वही काम कर रही है।"

भाजपा का दावा- नेहरू के फैसले ने बोया विभाजन का बीज

उन्होंने कहा, "1923 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का संपूर्ण गायन होना था। मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने वॉकआउट किया। इसके बाद 1937 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित कर एक हिस्सा ही गाने का प्रस्ताव लाया गया। 1938 में नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना को लिखी चिट्ठी में 14 मांगों के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने वंदे मातरम के संपूर्ण पठन को रोक दिया।"

संबित पात्रा ने कहा, "पंडित नेहरू की ओर से 1937 में बोया गया, यही तुष्टिकरण का बीज आगे चलकर देश के विभाजन की वजह बना। कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो व्यवहार 15 अगस्त को रहा। इसके बाद जो कांग्रेस कार्य समिति में 1937 के प्रस्ताव को फिर से पारित किया गया। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से कहा है कि कांग्रेस यह जो विभाजन का बीज बोने की कोशिश कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे।"

वंदे मातरम पर महात्मा गांधी के पत्र का किया जिक्र

पात्रा ने कहा, "महात्मा गांधी ने स्वयं वंदे मातरम के बारे में लिखा था– 'इसका स्रोत क्या था और इसकी रचना कब और कैसे हुई, यह अलग बात है; लेकिन बंगाल के विभाजन के दिनों में यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली युद्धघोष बन गया था। यह साम्राज्यवाद विरोधी नारा था। जब मैं छोटा था और न आनंदमठ के बारे में जानता था, न उसके अमर रचयिता बंकिम के बारे में, तब भी वंदे मातरम ने मुझे अपने प्रभाव में ले लिया था।" उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी ने लिखा था– जब मैंने इसे पहली बार सुना और गाया, तो यह मुझे मंत्रमुग्ध कर गया। मैंने इसके साथ शुद्धतम राष्ट्रीय भावना को जोड़ा। मुझे कभी यह विचार नहीं आया कि यह हिंदुओं का गीत है या केवल हिंदुओं के लिए है। दुर्भाग्य से, आज हम बुरे दौर में आ गए हैं।'

संक्षेप

आयरन फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में अचानक लगी आग, 3 इंजीनियरों की मौत, एक मजदूर घायल

रांची। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित एक स्पंज आयरन फैक्टरी के कंट्रोल रूम में अचानक आग लग गई। हादसे में कई मजदूर झुलस गए। घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, मृतकों में तीनों इंजीनियर शामिल हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। झुलसे लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का इलाज जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जानकारी के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि कंट्रोल रूम में किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आग लगी होगी। हालांकि, आग की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा पर इंटरपोल का शिकंजा, जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड और भगोड़े गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। पुलिस के मुताबिक, साठा जाली पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था और लंबे समय से विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा है। संभल के पूर्व पुलिस अधीक्षक और वर्तमान में बिजनौर के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शुक्रवार को बताया कि साठा को अदालत पहले ही भगोड़ा अपराधी घोषित कर चुकी है। उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की गई थी। जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (ष्टक्चढ्ढ) से इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने का अनुरोध किया था। पुलिस के अनुसार, साठा जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर दुबई भाग गया था। उसके परिवार के सदस्यों के दुबई आने–जाने की जानकारी भी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए सीबीआई को विस्तृत डोजियर सौंपा। इसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल के साथ समन्वय कर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया। बिश्नोई ने कहा कि अब साठा को गिरफ्तार कर उसे उस देश से भारत प्रत्यर्पित कराने की कोशिश की जाएगी, जहां वह मौजूद है। इसके बाद 24 नवंबर 2024 की हिंसा के मामले के अलावा उसके खिलाफ दर्ज अन्य आपराधिक मामलों में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, साठा के खिलाफ उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (ह्लष्टक्र) में करीब 55 से 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें वाहन चोरी समेत कई संगठित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस का आरोप है कि वह विदेश में रहते हुए भी आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था।

अखिलेश की 'चवन्नी' टिप्पणी पर जयंत चौधरी का पलटवार

'ये जाट समुदाय का अपमान', बोले-ऐसा अहंकार केवल पतन लाता है

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों पूर्व सहयोगी अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में 'चवन्नी' वाली टिप्पणी की थी। इस पर राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने अब तीखा पलटवार किया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह टकराव अखिलेश यादव के 'चवन्नी' वाले कटाक्ष को लेकर है। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा था, ₹जाने कहां-कहां से आ गए थे लोग गठबंधन बनाने।'

यादव ने आगे कहा कि 'हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था, तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।' उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। लेकिन उनकी यह टिप्पणी जयंत चौधरी के लिए मानी गई। यह 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान की बात है। तब जयंत चौधरी ने भाजपा की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था।

उन्होंने कहा था कि वह 'चवन्नी' नहीं हैं जिसे आसानी से पलटा जा सके। अखिलेश ने यह भी कहा कि कई लोग सपा छोड़कर चले गए हैं। उनकी पार्टी ने जनता से जुड़ने का संकल्प लिया है। सपा सामाजिक न्याय स्थापित करने और लोगों पर भरोसा करने को प्रतिबद्ध है।

यह विवाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया है। रालोद ने अखिलेश यादव के बयान को किसान नेता चौधरी चरण सिंह की विरासत का अपमान कहा। साथ ही जाट समुदाय का भी अपमान बताया गया है।

जयंत चौधरी का जवाब

शुक्रवार को रालोद के अध्यक्ष और केंद्री मंत्री जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सस्ती राजनीतिक टिप्पणियां करनी थीं, तो कम से कम उनका नाम लेना चाहिए था। जयंत चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट किया।

उन्होंने लिखा, 'अगर आपको कुछ सस्ते शब्द इस्तेमाल करने थे, तो कम से कम मेरा नाम लेकर कहते।' जयंत चौधरी ने अपनी पोस्ट में जोड़ा, 'जाट समुदाय को निशाना बनाना और कहना कि हमने ABCD सिखाई?' उन्होंने यादव का नाम लिए बिना कहा कि ऐसा अहंकार केवल पतन लाता है। चौधरी ने कहा, 'मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं ऐसा आचरण सिर्फ़ पतन लाता है!'

समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़े थे। इस गठबंधन के तहत रालोद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने इनमें से आठ सीटों पर जीत हासिल की थी। यह रालोद के लिए एक बड़ी बढ़त थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। तब रालोद ने पूरे उत्तर प्रदेश में 277 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी।

अखिलेश यादव ने अपनी टिप्पणी से संकेत दिया कि सपा के साथ गठबंधन ने रालोद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन वापस पाने में मदद की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। वह वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं।

रालोद की तीखी प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के मंत्री और रालोद नेता अनिल कुमार ने यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे ₹अत्यधिक आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण₹ बताया। अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी केवल जयंत चौधरी का अपमान नहीं है। यह चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और पूरे किसान समुदाय का भी अपमान है। कुमार ने कहा, ₹समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए।₹ आज समाजवादी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व में चौधरी चरण सिंह परिवार का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसान समुदाय 2027 के विधानसभा चुनाव में इस कथित अपमान का लोकतांत्रिक जवाब देगा।

मायावती का सपा पर हमला, बोलीं– 'चवन्नी से रुपया' वाला बयान अमर्यादित और शर्मनाक, जाट समाज से मांगे माफी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा प्रमुख के राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) और उसके नेता को लेकर दिए गए 'चवन्नी से रुपया बना दिया' वाले बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताया। मायावती ने कहा कि इस बयान के लिए सपा नेतृत्व को रालोद, उसके नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ जाट समाज से भी माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति में विरोधी दलों के साथ-साथ सहयोगी दलों के प्रति भी संकीर्णता और जातिवादी रवैया रहा है। उनके मुताबिक, इसका राजनीतिक लाभ कई मौकों पर भाजपा को मिला और धर्मनिरपेक्ष ताकतें कमजोर हुईं।

सपा पर गंभीर आरोप लगाए

उन्होंने 1993 में सपा-बसपा गठबंधन बनने और बाद में टूटने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। मायावती ने इसे अपने खिलाफ हत्या के षड्यंत्र से जोड़ते हुए सपा पर गंभीर आरोप लगाए।बसपा प्रमुख ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद गठबंधन टूट गया और यह सपा के अहंकारी तथा स्वार्थी रवैये का परिणाम था।

पीडीए को लेकर भी निशाना साधा

मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अपने राजनीतिक हित के अनुसार पीडीए में 'पी' की अलग-अलग व्याख्या करती है। साथ ही उन्होंने सपा की पिछली सरकारों पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मणों, के हितों की अनदेखी तथा कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से सपा को सत्ता से दूर रखने की अपील की और सर्वसमाज को उसकी कथित संकीर्ण एवं जातिवादी राजनीति से सावधान रहने को कहा।

दोस्त का कत्ल, लाश के 5 टुकड़े : सिर, धड़ और हाथ–पैर किए अलग, प्लास्टिक के बोरे में पैक कर इसलिए गोबर में दबाया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

वाराणसी। वाराणसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। वाराणसी के सिगरा थाना इलाके के शिवपुरवा से छह अगस्त से लापता ईशू कन्नौजिया (19) की उसके तीन दोस्तों ने ही गला काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार की रात आरोपियों प्रदीप और उसके सगे भाई रामकृष्ण, मित्र रोहित को गिरफ्तार करके वारदात का खुलासा किया।

ईशू का शव पांच टुकड़ों में करके प्लास्टिक के बोरे में भरकर गोबर भरे गड्ढे में फेंका गया था। आरोप है कि पिटाई का बदला लेने के लिए दोस्तों ने सात अगस्त को वारदात को अंजाम दिया और रात में शव को ठिकाने लगाया था। आरोपियों की निशानदेही पर लहरतारा मार्ग स्थित खखड़िया पोखरी के पास रेलवे के खंडहरनुमा क्वार्टर के पास गोबर के गड्ढे से प्लास्टिक के बोरे में भरे गए शव को शुक्रवार की रात बरामद किया गया।

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि शराब पिलाने के बाद ईशू की हत्या की थी। चापड़ से पांच टुकड़े में शव को काटा गया था। शिवपुरवा क्षेत्र निवासी ईशू कन्नौजिया छह अगस्त की शाम को घर से निकला था लेकिन रात तक नहीं लौटा।

परिजन ने 17 अगस्त को थाने में दी थी तहरीर

वह अक्सर रात में घर नहीं आता था इसलिए परिजनों ने उस दिन बहुत खोजबीन नहीं की। अगले दिन दोपहर तक नहीं आया, तो परिजन परेशान हो गए। इस बीच परिजनों ने उसके दोस्तों से पता किया। रिश्तेदारी में भी खोजबीन कराई लेकिन कहीं से सुराग नहीं मिल सका।

प्रदीप ने चापड़ से ईशू का गला काटा, सिर और धड़ अलग किए

दस दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद परिजनों ने 17 अगस्त को सिगरा थाने में तहरीर दी। थाने की

पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सिगरा इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रदीप और रामकृष्ण उर्फ रामकिशन दोनों सगे भाई हैं। जबकि रोहित उनका मित्र है।

पूछताछ में रोहित और रामकृष्ण ने बताया कि तीन अगस्त को शराब पीने के दौरान ईशू ने प्रदीप की पिटाई कर दी थी। इस पिटाई से प्रदीप आहत था। प्रदीप ने बदला लेने की नियत से ईशू की हत्या की साजिश रची।

छह अगस्त की रात में ईशू को बुलाया गया। सात अगस्त को दिन में उसे लेकर सभी लहरतारा-महमूरगंज पानी टंकी के पास रेलवे के खंडहरनुमा क्वार्टर गए। ईशू को खूब शराब पिलाई गई। इसके बाद तीनों ने ईशू की पिटाई की।

रोहित और रामकृष्ण ने ईशू के दोनों हाथ पकड़े और प्रदीप ने चापड़ से उसका गला काट दिया। सिर और धड़ दोनों अलग-अलग कर दिए। बताया जा रहा है कि हाथ-पैर भी अलग किए थे। दोपहर 1:30 बजे घटना को अंजाम दिया गया। शव को पांच टुकड़े में काटने के बाद प्लास्टिक के बोरे में शव को तीनों ने भरा।

यूट्यूब पर देखा हत्या का तरीका

पुलिस ने बताया कि ईशू के दोस्तों ने हत्या के बाद बड़े ही सफाई से शव को ठिकाने लगाया। ऐसी जगह चुनी जहां किसी को शंका तक न हो सके। गोबर के गड्ढे में शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर फेंका गया ताकि आसपास के लोगों को दुर्गंध न महसूस हो सके। जब लोग गुजरे तो उन्हें गोबर की दुर्गंध महसूस हो। प्रदीप ने यूट्यूब पर ये तरीका देखा था। प्रदीप ने पुलिस को बताया कि

> छह अगस्त से लापता ईशू की 17 अगस्त को गुमशुदगी परिजनों ने सिगरा में दर्ज कराई थी। पुलिस की एक टीम ने छानबीन की है। दोस्त प्रदीप ने ही उसे बुलाया और शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। प्रदीप, उसके भाई रामकिशन और दोस्त रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
>
> **-वैभव बांगर, एडीसीपी काशी जोन**

ईशू को वह काफी दिनों से जानता था। ईशू हमेशा उस पर धौंस जमाता था।

ईशू पर दर्ज थे 5 आपराधिक मामले

सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि ईशू मनबढ़ किस्म का था। उस पर सिगरा और भेलूपुर थाने में मारपीट समेत अन्य आरोपों में पांच प्राथमिकी दर्ज थी। उधर, घटना की जानकारी मिलते ही शिवपुरवा में ईशू के परिजनों में कोहराम मच गया। एहतियातन थाने की फोर्स तैनात की गई। रात में डीसीपी काशी, एडीसीपी समेत अन्य अधिकारियों ने घटना के बाबत जानकारी ली।

प्रदीप की अंतिम कॉल से खुला राज, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने भी फंसाया

सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने एक टीम गठित करके ईशू के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई। ईशू के फोन पर अंतिम कॉल शिवपुरवा के रहने वाले दोस्त प्रदीप की थी। इसी आधार पर पुलिस ने प्रदीप को उठाय लिया।

शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर फेंका गया है। शुक्रवार की रात 10 बजे सिगरा पुलिस ने शव को बरामद किया। प्लास्टिक के बोरे को खुलवाया गया तो गोबर की वजह से शव सड़-गल चुका था। शव को मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा स्थित मुर्दाघर में रखवा दिया गया।

कस्तूरबा विद्यालय में एसडीएम का औचक निरीक्षण, 90 छात्राएं मिलीं मौजूद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बल्दीराय/सुलतानपुर। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय धनपतगंज में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब बल्दीराय के एसडीएम प्रभात सिंह ने विद्यालय में अचानक पहुंचकर व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम के अचानक निरीक्षण से विद्यालय प्रशासन में भी सक्रियता दिखाई दी।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था, छात्राओं की उपस्थिति, साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता, स्टेशनरी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से भी बातचीत कर विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं और किसी प्रकार की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। एसडीएम ने विद्यालय परिसर में चल रहे विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन बाउंड्रीवाल, कंप्यूटर कक्ष तथा शौचालय निर्माण की स्थिति देखी और संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कुल 90 छात्राएं उपस्थित मिलीं। छात्राओं की उपस्थिति और व्यवस्थाओं की स्थिति देखने के बाद एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय में रहने वाली छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। एसडीएम ने विद्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने तथा छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान बीईओ धनपतगंज/बल्दीराय श्याम बिहारी, विद्यालय की वार्डन प्रतिमा सिंह और संदीप पांडे समेत विद्यालय से जुड़े अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम के औचक निरीक्षण को लेकर विद्यालय में दिनभर चर्चाओं का दौर रहा।

सफल सर्जरी कि हो रही सराहना: इमरजेंसी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर निकाला सड़ा हुआ पित्ताशय

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। राजकीय स्वशासी मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर के डॉक्टरों की टीम ने त्वरित और सफल इमरजेंसी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी (दूरबीन विधि) करके मरीज को नई जिंदगी दी है। पूरे पेट और आंतों की गहराई से जांच के बाद लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी विधि से दूरबीन द्वारा सड़ चुके गॉलब्लाडर को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पेट की पूरी सफाई की गई। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार है और उन्हें विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है। समय पर सही फैसले और दूरबीन विधि से की गई इस सफल सर्जरी के लिए मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ सर्जिकल टीम की सराहना की जा रही है।

अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, मरीज को अत्यंत गंभीर हालत में इमरजेंसी विभाग में लाया गया था। जांच के बाद सर्जरी विभाग

की टीम ने तत्काल इमरजेंसी लेप्रोस्कोपिक एक्सप्लोरेशन (दूरबीन द्वारा पेट की आंतरिक जांच व सर्जरी) करने का निर्णय लिया। मरीज को गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए मरीज का तुरंत क्लिनिकल मूल्यांकन किया और सीटी स्कैन कराया। जांच में पेट के भीतर पित्त फैलने (बिलियस पेरिटोनिटिस) की पुष्टि हुई, जो कि एक जानलेवा स्थिति होती है।

ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि मरीज का पित्ताशय पूरी तरह से सड़ चुका था (गैंग्रीनस जीबी) और पेट के चारों हिस्सों (क्वाड्रेंट्स) में पित्त फैल चुका था। डॉक्टरों ने पूरी आंत का बारीकी से निरीक्षण किया और सुरक्षित रूप से सड़े हुए पित्ताशय को दूरबीन विधि द्वारा बाहर निकाला (लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी)। यह जटिल और जीवनरक्षक ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टरों के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में पूरा हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुप्रीत वर्मा, डॉ. आकाश श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. आदित्य गंगवार सीनियर रेजिडेंट, डॉ अमित वर्मा जूनियर रेजिडेंट 'एनेस्थेटिस्ट डॉ. राजेश, ओटी असिस्टेंट प्रशांत, हेड नर्स शीलम सिस्टर एवं समस्त नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ। सफल सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है।

बदायूं में बाढ़ : खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, रामगंगा और अरिल नदी भी उफनाई, रपटा पुल डूबे

आर्यावर्त संवाददाता

बदायूं। बदायूं जिले में गंगा सहित अन्य नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गंगा का जलस्तर उसहैत इलाके में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं, दातागंज तहसील क्षेत्र में रामगंगा और अरिल नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांवों के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं।

उसहैत इलाके के कदमनगला, जटा, ठाकुरी नगला, प्रेमीनगला, बेहटी, असमय रफतपुर और अहमद नगर बछौरा गांवों के खेतों में पानी घुस गया है। यदि जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो एक-दो दिन में इन गांवों की बस्तियों में भी पानी पहुंच सकता है। कदमनगला के ग्रामीण सबसे अधिक भयभीत हैं। यह गांव आधे से ज्यादा खाली हो चुका है।

कटान के कारण सैकड़ों बीघा

जमीन नदी में समा गई है। जटा और प्रेमीनगला को जाने वाले मार्ग पर पानी आने से आवागमन प्रभावित है। दातागंज इलाके में अरिल नदी पर हरें नगला और गड़िया के बीच बने रपटा पुल पर तीन से चार फुट पानी है। इससे पैदल, दोपहिया वाहन और कारों का आवागमन बंद हो गया है। लोग ट्रैक्टर-ट्रालियों और नावों से आवागमन कर रहे हैं।

इस मार्ग पर आवागमन बाधित

दातागंज से शाहजहांपुर को जाने वाले नगरिया खनू लालपुर खादर-गड़िया रंगीन मार्ग पर रामगंगा नदी का पानी आ गया है। यहां रपटा पुल से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। रामगंगा के हजरतपुर से लालपुर खादर गड़िया रंगीन जाने वाले मार्ग पर बने रपटा पुल पर भी पानी है। भेड़ा मार्ग पर भी पानी होने की जानकारी मिली है। रामगंगा ने हररामपुर में अधिक दिक्कतें पैदा की हैं।

हजारों लोग परेशान

रपटा पुलों पर पानी आने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। इससे हजारों लोग परेशान हैं। अरिल नदी रपटा पुल से करीब दो किलोमीटर आगे रम्पुरा गांव के पास रामगंगा नदी में मिल जाती है। यह स्थिति स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।

डीएम इंद्रजीत सिंह के यूपीनेडा अनुभव से जुड़ा हाइड्रोजन संवाद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जापान के यामानाशी प्रिफेक्चर के गवर्नर कोतारो नागासाकी के नेतृत्व में आया हाईप्रोफाइल जापानी प्रतिनिधिमंडल शनिवार को सुल्तानपुर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जापानी मेहमानों का स्वागत किया गया।

जापान से आए इस प्रतिनिधिमंडल का उत्तर प्रदेश दौरा निवेश, तकनीकी सहयोग, पर्यटन, कौशल विकास और भारत-जापान के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हो रहा है। यामानाशी के गवर्नर कोतारो नागासाकी के नेतृत्व में आया यह प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रमुख स्थलों का दौरा कर रहा है। हाल में प्रतिनिधिमंडल ने आगरा में ताजमहल का भ्रमण भी किया था।

सुल्तानपुर में जापानी प्रतिनिधिमंडल के आगमन के दौरान जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की पूर्व जिम्मेदारियां भी चर्चा में रहीं। इंद्रजीत सिंह सुल्तानपुर का जिलाधिकारी बनने से पहले ऊर्जा विभाग में विशेष सचिव तथा यूपीनेडा के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और नई ऊर्जा तकनीक से जुड़े विषयों पर जापानी प्रतिनिधियों के साथ संवाद के लिए उनका पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जापान के यामानाशी प्रतिनिधिमंडल की उत्तर प्रदेश यात्रा में भी ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, तकनीकी सहयोग और निवेश प्रमुख विषयों में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इसी पृष्ठभूमि में डीएम इंद्रजीत सिंह और जापानी प्रतिनिधियों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन एवं स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े संभावित सहयोग और अवसरों को लेकर बातचीत हुई। हालांकि यह मुलाकात पुर्णतया निजी थी और किसी विशेष परियोजना या निवेश की औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है। जापानी प्रतिनिधिमंडल के सुल्तानपुर पहुंचने को स्थानीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। जापान और उत्तर प्रदेश के बीच हाल के वर्षों में उद्योग, पर्यटन, व्यावसायिक सहयोग, कौशल विकास और ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच उद्योग, पर्यटन और व्यावसायिक शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता भी हुआ था। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यामानाशी यात्रा के दौरान भी ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी और तकनीकी आदान-प्रदान को लेकर सहयोग आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने उस समय यामानाशी के गवर्नर कोतारो नागासाकी के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश में जापानी उद्योगपतियों के बड़े प्रतिनिधिमंडल के आने का स्वागत किया था। सुल्तानपुर में जापानी प्रतिनिधिमंडल का आगमन पूर्व निर्धारित नही था, वाराणसी के रास्ते में बड़ा शहर और यहा तैनात डीएम से पुरानी जान-पहचान ने कुछ समय के लिए यहां ठहरना सबके मन में जिज्ञासा भर दी।

मातृत्व अवकाश को लेकर बदले नियम, स्कूल के रसोइयों का बढ़ा मानदेय

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब मातृत्व अवकाश के लिए दो बच्चों की उम्र के बीच दो साल का अंतर होना अनिवार्य नहीं होगा। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन शनिवार को वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

अब तक की व्यवस्था में दूसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ लेने के लिए दोनों बच्चों की उम्र में कम से कम दो साल का अंतर होना जरूरी था। इससे कई मामलों में महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश से वंचित होना पड़ रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में ऐसे ही एक मामले में दो बच्चों के बीच उम्र का

अंतर दो साल से कम होने के आधार पर मातृत्व अवकाश से इन्कार करने को गलत ठहराया था और महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश देने और उससे जुड़े सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया था।

अदालत के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश के नियम में मौजूद दो साल के अंतर की बाध्यता को ही समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से अब दो बच्चों के बीच उम्र का अंतर दो साल से कम होने पर भी पात्र महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे मातृत्व अवकाश से जुड़े मामलों में अनावश्यक विवाद भी कम होंगे।

प्रदेश के 3.50 लाख रसोइयों को तोहफा, 1000 रुपये बढ़ा मानदेय

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले 3.50 लाख रसोइयों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने उनका मानदेय 1000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मानदेय बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। अब उन्हें हर महीने (साल में 10 महीने) 3000 रुपये मानदेय सितंबर से लागू किया जाएगा। यूपी में 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में 1.46 करोड़ छात्रों को मिड-डे-मील दिया जा रहा है। रसोइयों को पहले एक हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाता था। 2019 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया और 2022 में मासिक मानदेय बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया था। रसोइयों को अभी 200 रुपये मासिक मानदेय के साथ ही 500 रुपये यूनिफॉर्म व 400 रुपये ग्लब्स के लिए भी दिए जाते हैं। सरकार ने चुनाव से पहले रसोइयों की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया है। इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड का भी वितरण करेंगे।

नवाबगंज और जहांगीराबाद में बनेंगे नए बस स्टेशन

बरेली के नवाबगंज और बुलंदशहर के जहांगीराबाद में नए बस स्टेशन बनने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों जगह बस स्टेशन के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी मिल गई है। नवाबगंज में जमीन परिवहन निगम को निशुल्क पट्टे पर दी जाएगी, जबकि जहांगीराबाद में राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। नवाबगंज में बस स्टेशन की जरूरत लंबे समय से थी। पुराने बस अड्डे की जमीन के अनुपयोगी होने के बाद नए स्थान पर बस स्टेशन बनाने की कवायद चल रही थी। वहीं जहांगीराबाद में भी बस स्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। वर्ष 2019 में भी यहां बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार होने और जमीन नहीं मिलने की बात सामने आई थी। दोनों स्थानों पर जमीन उपलब्ध होने के बाद बस स्टेशन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

जेन जी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने राजभवन मार्च कर घेराव किया

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। जेन जी छात्रों के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और ए.के.-47 से गोली चलाए जाने तथा छात्र-छात्राओं के साथ पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के विरोध में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य के अध्यक्ष दीपक शिवहरे के नेतृत्व में शनिवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन चौक से राजभवन तक मार्च किया और राजभवन का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की।मार्च में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी उत्तर प्रदेश एवं पूर्व मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम, राष्ट्रीय सचिव जगदीश चन्द्र जांगीड़ और अब्दुल हन्नान, सांसद राकेश राठौर, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेन जी छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

38 प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने नगर निगम की व्यवस्थाओं और परियोजनाओं का किया स्थलीय अध्ययन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ की ओर से आयोजित पीसीएस फेज-1 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को 38 प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने नगर निगम लखनऊ की विभिन्न व्यवस्थाओं और परियोजनाओं का स्थलीय अध्ययन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 अगस्त से 16 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।अध्ययन भ्रमण की शुरुआत सुबह 6:30 बजे नगर निगम जोन-4 के मॉडल वार्ड से हुई। प्रशिक्षु अधिकारियों ने यहां डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, कचरा पृथक्करण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नगर निगम अधिकारियों ने वार्ड स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था और कचरा प्रबंधन की कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षु

अधिकारियों को जानकारी दी।इसके बाद प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने जोन-4 स्थित भैंसौरा ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया। यहां उन्हें कचरे के संग्रहण, हस्तांतरण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।अध्ययन भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने भरवारा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। जलकल विभाग के अधिकारियों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली, सीवेज के उपचार और इससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया।वेस्ट-टू-वंडर की अवधारणा को समझने के लिए प्रशिक्षु अधिकारियों ने यूपी दर्शन पार्क का भ्रमण किया। यहां उन्होंने अपशिष्ट पदार्थों के रचनात्मक उपयोग और उससे संबंधित व्यवस्थाओं का स्थलीय अवलोकन किया।इसके बाद प्रशिक्षु अधिकारियों ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। यहां उन्हें तकनीक के माध्यम से नगरीय सेवाओं की निगरानी, विभिन्न गतिविधियों की मॉनिटरिंग और शहर की व्यवस्थाओं के संचालन के संबंध में जानकारी दी गई।भ्रमण के अगले चरण में प्रशिक्षु अधिकारियों ने नगर निगम के जोन-3 कार्यालय में कर व्यवस्था से संबंधित प्रस्तुति का अवलोकन किया। अधिकारियों ने कर निर्धारण, कर संग्रह और कर से जुड़े कार्यों की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।अध्ययन भ्रमण के अंतिम चरण में प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने जोन-2 स्थित ऐशबाग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। जलकल विभाग की ओर से प्रशिक्षु अधिकारियों को जल शोधन, जल आपूर्ति और प्लांट की कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई।नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी नन्द किशोर को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नामित किया गया था।

फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर 27 .30 लाख रुपये के राजस्व को चूना लगाने वाले गिरोह का खुलासा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी फर्म तैयार कर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने और उसे दूसरी फर्मों को पास-ऑन कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ लखनऊ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से छह मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, फर्जी लेन-देन के इस नेटवर्क से सरकारी राजस्व को करीब 27 लाख 30 हजार रुपये की क्षति पहुंचाई गई।पुलिस के मुताबिक, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ तरुण गाबा और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार के निर्देश पर फर्जी फर्मों के माध्यम से जीएसटी कर चोरी एवं सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों और गिरोहों के विरुद्ध

विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल कुमार यादव और अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव के निर्देशन में क्राइम ब्रांच लखनऊ को यह सफलता मिली।मामला एम/एस घनश्याम एंटरप्राइजेज से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, 30 अगस्त 2025 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर फर्म के संबंध में जांच शुरू की गई थी। उक्त फर्म ने अनब्रॉट लेड वेस्ट, पैरिंग्स तथा प्लास्टिक के स्क्रैप की खरीद-बिक्री के लिए जीएसटी पहचान संख्या प्राप्त की थी। जांच के दौरान फर्म के पंजीकरण और कारोबार से संबंधित दस्तावेजों में कई अनियमितताएं सामने आईं।जांच में पता चला कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर विभिन्न फर्मों और कंपनियों के साथ कागजी लेन-देन दर्शाया गया और उसके आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा तथा उसे आगे पास-ऑन किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविक कारोबार के विपरीत फर्जी आईटीसी का नेटवर्क तैयार कर जीएसटी कर का अपवंचन किया जा रहा था।

हुसैनगंज पुलिस ने गैर जमानती वारंट के तहत वांछित आरोपी युसूफ को रामलीला मैदान के पास से किया गिरफ्तार

लखनऊ। हुसैनगंज पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में वांछित चल रहे आरोपी युसूफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को रामलीला मैदान, पुराना किला हुसैनगंज के पास से पकड़ा और आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-18, जनपद लखनऊ की अदालत द्वारा वाद संख्या 1015/2024 से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 0154/2023 में आरोपी युसूफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। यह मुकदमा थाना हुसैनगंज में धारा 307 और 504 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज है।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चौक थाने के मुकदमे में दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए की जा रही प्रभावी पैरवी का असर सामने आया है। चौक थाने में वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमे में माननीय न्यायालय एडीजे-18, लखनऊ ने अभियुक्त मनीष श्रीवास्तव को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इनमें दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है।पुलिस के अनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 335/2014 धारा 419, 420, 384, 342, 376, 506 और 354क भारतीय दंड संहिता से संबंधित था। मामले में अभियुक्त मनीष श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद, निवासी सुन्दरनगर उमरपुर, थाना कोतवाली जौनपुर, जनपद जौनपुर को न्यायालय ने दोषसिद्ध किया।अभियुक्त को धारा 419 भारतीय दंड संहिता में दो वर्ष का साधारण कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 420 में तीन वर्ष का साधारण कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 384 में दो वर्ष का साधारण कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। ्यायालय के आदेश के अनुसार सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को दंडादेश में समायोजित किया जाएगा।

सीईआईआर पोर्टल की मदद से लखनऊ पुलिस ने बरामद किए 100 खोए मोबाइल फोन, 18 लाख रुपये के मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ।पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की साइबर सेल, जोन-दक्षिणी ने खोए और गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल की टीम ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से विभिन्न जनपदों और राज्यों में ट्रेस किए गए 100 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपये है। पुलिस ने सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को वापस कर दिए।मोबाइल फोन वापस मिलने के बाद स्वामियों के चेहरों पर खुशी लौट आई। लोगों ने लखनऊ पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए साइबर सेल की टीम का आभार जताया और पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पुलिस के अनुसार, पुलिस

आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ तरुण गाबा और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर जनता के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मोबाइल फोन की गुमशुदगी से संबंधित विवरण सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज कर उन्हें तकनीकी माध्यम से ट्रेस करने के निर्देश दिए गए थे।पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) मो. मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वसंथ कुमार के निर्देशन में साइबर सेल, जोन-दक्षिणी की टीम ने दक्षिणी जोन के सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क की सहायता से विभिन्न लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से ट्रेस किया।जांच के दौरान मोबाइल फोन की लोकेशन विभिन्न जनपदों और राज्यों में पाई गई। इसके बाद दक्षिणी जोन के संबंधित थानों की साइबर टीमों के साथ समन्वय स्थापित कर इन मोबाइल फोन को बरामद किया गया। बरामद मोबाइल फोन के वास्तविक स्वामियों को बुलाकर आवश्यक सत्यापन के बाद उनके सुपुर्द कर दिया गया।साइबर सेल ने कार्रवाई के दौरान विभिन्न कंपनियों के कुल 100 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपये है। मोबाइल फोन बरामद करने वाली टीम में साइबर सेल, जोन-दक्षिणी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टीम शामिल रही।पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक खोए हुए कुल 347 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 61 लाख रुपये है। बरामद सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को सुपुर्द किए गए हैं।पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल फोन गिरने या खोने की स्थिति में तत्काल प्ले स्टोर से यूपी कॉप ऐप डाउनलोड कर साइन अप एवं लॉगिन करें। इसके बाद एफआईआर सेक्शन में जाकर रजिस्टर लॉस्ट आर्टिकल के माध्यम से मोबाइल गुम होने का विवरण दर्ज करें। इसके बाद सीईआईआर, साइबर एंड ई-चालान/पासपोर्ट स्टेटस सेक्शन में जाकर सीईआईआर (खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करना) विकल्प पर आवश्यक विवरण भरें। साथ ही तत्काल अपने निकटतम पुलिस थाने से संपर्क करें। समय रहते शिकायत दर्ज कराने और सीईआईआर पोर्टल पर विवरण उपलब्ध कराने से खोए या चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस कर बरामद करने में पुलिस को मदद मिलती है।

बीकेटी पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित आरोपी को घर से दबोचा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। थाना बीकेटी पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित चल रहे 24 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को उसके ग्राम कोटवा स्थित घर से घेराबंदी कर पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और उसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस द्वारा की जा रही है।पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त 2026 को सीतापुर जनपद के थाना रेउसा क्षेत्र के ग्राम पारपुरवा निवासी जयराम पुत्र चन्द्रिका प्रसाद ने थाना बीकेटी में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया था कि उनकी बहन बट्टू का विवाह करीब एक वर्ष पूर्व सतीश गौतम उर्फ भूरे पुत्र रामचन्दर गौतम, निवासी ग्राम कोटवा, थाना बीकेटी, लखनऊ के साथ हुआ था। आरोप है कि दहेज के लालच में ससुरालीजनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।तहरीर के आधार पर थाना बीकेटी में मुकदमा अपराध संख्या 327/2026 के तहत धारा 85, 80(2) बीएनएस तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त, बीकेटी द्वारा की जा रही है।पुलिस के मुताबिक, 22 अगस्त को मुकदमे में नामजद वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे से संबंधित वांछित आरोपी सतीश गौतम उर्फ भूरे अपने ग्राम कोटवा स्थित घर में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे और गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सतीश गौतम उर्फ भूरे पुत्र स्वर्गीय रामचन्दर गौतम, निवासी ग्राम कोटवा, थाना बीकेटी, लखनऊ, उम्र करीब 24 वर्ष के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना बीकेटी में मुकदमा अपराध संख्या 124/2026 में धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, मुकदमा अपराध संख्या 497/2019 में धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता तथा मुकदमा अपराध संख्या 0168/2026 में धारा 329(3) बीएनएस एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा थाना जानकीपुरम में मुकदमा अपराध संख्या 150/2022 के तहत धारा 392, 411 भारतीय दंड संहिता का मामला भी दर्ज है। पुलिस उसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।

संक्षेप

काकोरी में 21 वर्षीय युवक ने बाग में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच

लखनऊ। काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम समदा में शनिवार सुबह एक 21 वर्षीय युवक ने घर के पीछे स्थित बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।पुलिस के अनुसार, ग्राम समदा निवासी पंकज पुत्र रामसनेही ने सुबह करीब 7:30 बजे सूचना दी कि उसके भाई चंद्रशेखर पुत्र रामसनेही, उम्र करीब 21 वर्ष, ने घर के पीछे स्थित बाग में फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची।मौके पर पुलिस को जानकारी मिली कि चंद्रशेखर ने बबूल के पेड़ पर दुपट्टे के सहारे फांसी लगाई थी। परिजनों और आसपास के लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा गया। घटना की जानकारी के बाद फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की।पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजन मौके पर मौजूद हैं। पुलिस द्वारा मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

नाका हिंडोला पुलिस ने चारबाग से दिल्ली जाने की तैयारी कर रही दो नाबालिग बहनों को सकुशल परिजनों से मिलाया

लखनऊ। नाका हिंडोला पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान सजगता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए घर से नाराज होकर बिना बताए निकलीं दो नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की तत्परता से दोनों बच्चियों को सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया जा सका।पुलिस के अनुसार, 21 अगस्त 2026 की रात थाना नाका हिंडोला पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों की नजर सड़क किनारे घूम रही दो नाबालिग लड़कियों पर पड़ी। दोनों परेशान दिखाई दे रही थीं। संदेह होने पर पुलिसकर्मियों ने उनसे रात के समय वहां घूमने का कारण पूछा।पूछताछ में दोनों लड़कियों ने बताया कि वे थाना महाराजगंज, जनपद रायबरेली क्षेत्र की रहने वाली हैं और परिजनों की किसी बात से नाराज होकर बिना बताए घर से निकल आई थीं। दोनों रायबरेली डिपो से चारबाग पहुंची थीं और चारबाग से दिल्ली जाने वाली बस से दिल्ली जाने की तैयारी में थीं।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मी दोनों नाबालिगों को सुरक्षित पिंक बूथ-09, चारबाग थाना नाका हिंडोला लेकर पहुंचे और तत्काल उनके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने के कुछ समय बाद परिजन पिंक बूथ पहुंचे। अपनी बच्चियों को सकुशल देखकर परिजनों ने राहत की सांस ली और लखनऊ पुलिस की तत्परता एवं संवेदनशील कार्रवाई की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया।पुलिस ने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों नाबालिग लड़कियों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक रवीश भाटी, थाना नाका हिंडोला तथा महिला कांस्टेबल नीतू गंगवार, पिंक बूथ-09 चारबाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को वादिनी ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में तहरीर देकर बताया था कि बब्बू सिंह उसकी करीब 17 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना सुशांत गोल्फ सिटी में मुकदमा अपराध संख्या 469/2026 के तहत संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।नाबालिग की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के निर्देश पर तत्काल दो पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से नाबालिग की तलाश शुरू की।लगातार प्रयास के बाद पुलिस टीम ने नाबालिग को 20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली से बरामद कर लिया। इसके बाद अभियोग में नामजद आरोपी बब्बू सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश और तलाश की जा रही थी।इसी क्रम में 22 अगस्त 2026 को आरोपी बब्बू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

चार वर्षीय बच्ची से आपत्तिजनक कृत्य के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, जानकीपुरम पुलिस ने अर्जुन पार्क के पास से दबोचा

लखनऊ। जानकीपुरम थाना पुलिस ने करीब साढ़े चार वर्ष की बच्ची के साथ आपत्तिजनक कृत्य के मामले में वांछित चल रहे दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को 22 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 2:15 बजे अर्जुन पार्क के पास से हिरासत में लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को पीड़िता की मां ने थाना जानकीपुरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी करीब साढ़े चार वर्ष की पुत्री के साथ आपत्तिजनक कृत्य किया गया है। शिकायत के आधार पर थाना जानकीपुरम में मुकदमा अपराध संख्या 117/2026 के तहत धारा 65(2) बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक हरिदास चौरसिया को सौंपी गई थी।विवेचना के दौरान वादिनी के बयान, घटनास्थल के निरीक्षण और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर पुलिस टीम ने 18 अगस्त 2026 को मामले में नामजद आरोपी राम रतन पुत्र विसहुआ साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। आरोपी वर्तमान में जिला कारागार लखनऊ में निरुद्ध है।विवेचना को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर दूसरे आरोपी सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ साहू, उम्र करीब 21 वर्ष, को 22 अगस्त को अर्जुन पार्क के पास से हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी का वर्तमान पता सीतापुर रोड योजना, सेक्टर-सी, अलीगंज तथा आयुष विहार फेस-2, जानकीपुरम विस्तार, थाना जानकीपुरम, लखनऊ बताया गया है। उसका मूल निवास ग्राम रनवोड़, पोस्ट घोघरा, थाना एवं तहसील नवागढ़, जनपद बेमेतरा, छत्तीसगढ़ है। आरोपी एक होम्योपैथिक क्लीनिक में नौकरी करता है।

ताकि बचा रहे बचपन

किशोरों और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यूरोप के कई देशों ने पंद्रह या सोलह साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। इसका अगुआ होने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया को है, जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, एक्स यानी ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इसी तरह फ्रांस ऐसा कानून बनाने वाला यूरोप का पहला देश हो गया है। वहां की संसद ने पंद्रह साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का कानून पारित कर दिया है। हालांकि यह कानून खटाई में पड़ गया है। फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना है। अदालत का कहना है कि नाबालिगों पर प्रतिबंध लगाने के चक्कर में यह कानून असल में हर नागरिक पर सोशल मीडिया का उपयोग करने से पहले अपनी उम्र साबित करने का दबाव बनाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैंक्रो इस इस कानून के प्रबल समर्थक हैं। अदालत के फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि इस कानून को लागू करने के लिए अदालती फैसले के मद्देनजर जरूरी सुधार करके फिर से इसे संसद से पारित कराया जाएगा।

फ्रांस के इस फैसले से स्पष्ट है कि वह किशोरों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए पीछे नहीं हटने जा रहा है। जिस पश्चिमी दुनिया में सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ, जिन्होंने कभी अरब देशों में क्रांति के लिए सोशल मीडिया की सराहना की थी, अब उन्हें ही यह माध्यम अपने ही बच्चों का दुश्मन लगने लगा है। इसकी वजह है, वहां के बच्चों और किशोरों का बिगड़ता मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई का गिरता स्तर। इसकी वजह से अमेरिका तक में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिख रही है। प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी रायटर्स ने आईपोस कंपनी के साथ हाल ही में एक सर्वे किया है। इसमें शामिल 61 फीसद लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार को और सख्त निगरानी रखनी चाहिए। इस सर्वे में शामिल 66 प्रतिशत लोग तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उम्र के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया लागू करने पर जोर दिया है। वैसे अमेरिका के फ्लोरिडा जैसे कुछ राज्यों में चौदह साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक है।

दुनियाभर में बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य में आ रही गिरावट और बढ़ते मानसिक तनाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। कई शोधों से पता चला है कि लगातार स्क्रीन देखने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चे दूसरों की लाइफस्टाइल से खुद की तुलना करने लग रहे हैं। इससे उनमें हीन भावना, तनाव और डिप्रेशन बढ़ रहा है। इसकी वजह से उनकी नींद में कमी हो रही है। देर रात तक फोन चलाने के कारण भी बच्चों की सोने की आदत बिगड़ रही है। इससे उनमें चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है। जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया ऐप्स का अलगोरिदम ऐसा है, जिससे बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसके लत का शिकार हो रहे हैं. इससे वे स्क्रीन के आदी हो रहे हैं। कई बार कम उम्र के बच्चों के सामने आत्महत्या, हिंसा या उम्र के हिसाब से गलत सामग्री भी आती है। वैसे सोशल मीडिया का अलगोरिदम ऐसा है कि नकारात्मक, हिंसा प्रधान और सेक्स से जुड़ी खबरें और दृश्य जल्दी वायरल होते हैं। सोशल मीडिया ट्रोलिंग और अभद्र टिप्पणियों का बड़ा और आसान माध्यम बन गया है। इनकी वजह से बच्चे मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को फंसाने वाले अपराधी उन्हे आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इसीलिए दुनिया में कई देशों की सरकारें बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी में हैं। रोक लगाने वालों में इंडोनेशिया भी शामिल हो चुका है, जिसने मार्च 2026 से इसके नियम लागू कर दिए हैं। इनके अनुसार, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और रोब्लॉक्स जैसे हाई-रिस्क प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई है। इंडोनेशिया की तरह मलयेशिया ने भी ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगा रखी है। संयुक्त अरब अमीरात ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष तय की है। इससे कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बनाने पर यहां पूरी तरह रोक है। यूरोप के देश डेनमार्क में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ब्लॉक करने का कानून बन चुका है। बच्चों की उम्र की जांच के लिए सरकार डिजिटल एविडेंस ऐप पर काम कर रही है। इसी तरह ब्रिटेन की सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जो जनवरी 2027 से प्रभावी होने जा रही है। तुर्की में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून को मंजूरी मिल चुकी है, जिसे 2026 के अंत तक लागू किया जाना है।

विष्णु सरकार ने बढ़ाया किसानों का मान-खेती किसानी को मिला नया संबल

छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति परंपरा व आस्था से जुड़ा है हरेली तिहार

सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है।

छगन लाल लोन्हारे

प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गांव, गरीब और किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में हैं। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की इन ढाई साल के अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती-किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्यौहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदीकर न सिर्फ किसानों को मान बढ़ाया, बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। साथ ही किसानों के खाते में रमन सरकार के पिछले दो वर्ष का बकाया धान के बोनस 3716.38 करोड़ रूपए अंतरित कर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत गांवों में बसता है। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का व्यापार, उद्योग बढ़ेगा।

परंपरा के अनुसार वर्षों से छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले बढ़ई के घर में गेड़ी का ऑर्डर रहता था और बच्चों की जिद पर अभिभावक जैसे-तैसे गेड़ी भी बनाया करते थे। हरेली तिहार के दिन सुबह से तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं और खेती-किसानी, औजार, हल (नांगर), कुदाली, फावड़ा, गैंती को साफ कर घर के आंगन में मुरूम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ के चीला का भोग लगाया जाता है। अपने-अपने घरों में अराध्य देवी-देवताओं की साथ पूजा करते हैं। गांवों के गुड़ी में ठाकुरदेव की पूजा की जाती है।

हरेली पर्व के दिन पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधियुक्त आटे की लोंदी खिलाई जाती है। गांव में यादव समाज के लोग वनांचल जाकर कंदमूल लाकर हरेली के दिन किसानों को पशुओं के लिए वनौषधि उपलब्ध कराते हैं। गांव के सहाड़ादेव अथवा ठाकुरदेव के पास यादव समाज के लोग जंगल से लाई गई जड़ी-बूटी उबाल कर किसानों को देते हैं। इसके बदले किसानों द्वारा चावल, दाल आदि उपहार में यादवों को भेंट करने की परंपरा रही हैं।

सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओड़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा-भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आते तक खरीफ फसल आदि की खेती-किसानी का कार्य लगभग हो जाता है। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धोकर, धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ का चीला भोग लगाया जाता है। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण किया जाता है।

हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते है। गेड़ी बांस से बनाई जाती है। दो बांस में बराबर दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच से फाड़कर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। उसे नारियल रस्सी से बांधक़र दो पउआ बनाया जाता है। यह पउआ असल में पैर दान होता है जिसे लंबाई में पहले कांटे गए दो बांसों में लगाई गई कील के ऊपर बांध दिया जाता है। गेड़ी पर चलते समय रच-रच की ध्वनि निकलती हैं, जो वातावरण को और आनंददायक बना देती है। इसलिए किसान भाई इस दिन पशुधन आदि को नहला-धुला कर पूजा करते हैं। गेहूं आटे को गूंथ कर गोल-गोल बनाकर अरंडी या खम्हार पेड़ के पत्ते में लपेटकर गोधन को औषधि खिलाते हैं। ताकि गोधन को रोगों से बचाया जा सके। गांव में पौनी-पसारी जैसे राऊत, लोहार व बैगा हर घर के दरवाजे पर नीम की डाली खोंचते हैं। गांव में लोहार अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए चौखट में कील लगाते हैं। यह परम्परा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है।

पिहले के दशक में गांव में बारिश के समय कीचड़ आदि हो जाता था उस समय गेड़ी से गली का भ्रमण करने का अपना अलग ही आनंद रहता था। गांव-गांव में गली कांक्रीटीकरण से अब कीचड़ की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। हरेली के दिन गृहणियां अपने चूल्हे-चौके में कई प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाती है। किसान अपने खेती-किसानी के उपयोग में आने वाले औजार नांगर, कोपर, दतारी, टंगिया, बसुला, कुदारी, सब्बल, गैती आदि की पूजा कर छत्तीसगढ़ी व्यंजन गुलगुल भजिया व गुड़हा चीला का भोग लगाते हैं। इसके अलावा गेड़ी की पूजा भी की जाती है। शाम को युवा वर्ग, बच्चे गांव के गली में नारियल फेंक और गांव के खेल मैदान में कबड्डी आदि कई तरह के खेल खेलते हैं। बहु-बेटियां नए वस्त्र धारण कर सावन झूला, बिल्लस, खो-खो, फुगड़ी आदि खेल का आनंद लेती हैं।

हरेली तिहार सामाजिक समरसता का प्रतीक है यह केवल धार्मिक या कृषि पर्व नहीं है यह समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोडने का माध्यम है। गांव के लोग मिल-जुलकर पूजा और कार्यक्रमों का आयोजन करते है। इस दिन परिवार में सुख-समृद्धि की कामना के साथ ही प्रकृति और पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है।

लेखक संयुक्त संचालक जनसंपर्क हैं

व्यंग्य

रेलवे के बदहाल स्टेशन

रिपोर्ट इस सोच चुनौती देती है कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण बुनियादी यात्री सेवाओं की गारंटी कर देता है। जहां स्टेशनों को फिर से बनाया गया, उनमें से भी कई जगहों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

रेलवे स्टेशनों की दुर्दशा वैसे तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब उनकी बदहाली की विस्तृत तस्वीर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने भी सामने रखी है। गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं एवं स्वच्छता के हाल पर केंद्रित यह रिपोर्ट सभी 16 रेलवे जोनों के 512 ऐसे स्टेशनों के ऑडिट पर आधारित है। सीएजी ने स्टेशनों का चयन यात्रियों की आवाजाही और वहां से होने वाली कमाई को ध्यान में रखते हुए किया। उसने रेलवे डेटा, यात्री शिकायतों, यात्री प्रतिक्रियाओं, और रेलवे अधिकारियों के साथ मिल कर किए गए निरीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष है कि 89 प्रतिशत से अधिक स्टेशनों पर एक या अधिक न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की कमी है। और समस्या केवल छोटे स्टेशनों पर ही नहीं, बल्कि बड़े, उच्च-राजस्व और अधिक यात्री आवाजाही वाले स्टेशनों पर भी उसी तरह मौजूद है।

समस्या हैः सुविधाओं का ना होना और जो सुविधाएं मौजूद हैं, उनकी नाकाफी क्षमता तथा उनका रखरखाव ठीक ना होना। रिपोर्ट के मुताबिक 188 स्टेशनों पर पेय जल के पर्याप्त नल उपलब्ध नहीं थे, जो रेल मंत्रालय के इस दावे का खंडन करता है कि ऐसी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। रिपोर्ट इस सोच चुनौती देती है कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण खुद ही बुनियादी यात्री सेवाओं की गारंटी कर देता है। यहां तक कि जहां स्टेशनों को फिर से बनाया गया है और जिन्हें बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेशन समझा जाता है, उनमें से भी कई जगहों पर यात्रियों को पानी, पंखे, बैठने की जगह, शौचालय, और स्वच्छता की कमी आदि का सामना करना पड़ रहा है।

सार है कि भारतीय रेलवे के पास मानदंड, फंड और निगरानी के ढांचे तो मौजूद हैं, लेकिन उनके जरिए अमल असमान बना हुआ है। कारण जवाबदेही के सिस्टम का अभाव है। इस कारण सुविधाओं को मानदंडों के अनुसार प्रदान नहीं किया जाता, कार्यों के पूरा होने में देर होती है, मौजूद सुविधाओं का रखरखाव नहीं किया जाता, और कमियों को समयबद्ध कार्य योजनाओं के जरिए दूर नहीं किया जाता है। और इन सबको लेते हुए ही भारत ₹विकसित₹ होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है!

ब्लॉग

प्राकृतिक खेती - सतत कृषि और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

डॉ. देवेश चतुर्वेदी

भारत ने पिछले दशक में कृषि क्षेत्र में तेज प्रगति की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, पिछले 5 सालों में विकास दर 4त्न से अधिक रही है। खाद्यान्न, बागवानी और तेलहन फसलों का बंपर उत्पादन हुआ है। यह किसानों द्वारा नई तकनीकों को अपनाने और सिंचाई वाले क्षेत्र का विस्तार, बेहतर जल उपयोग दक्षता और समय पर व पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्धता जैसी सरकार की ठोस नीतियों के समर्थन का परिणाम है। बागवानी फसलों की हिस्सेदारी भी काफ़ी बढ़ रही है और इसकी विकास दर अपेक्षाकृत अधिक है।

हालांकि, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और प्रमुख फसलों की उत्पादकता में स्थिरता आ रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (एनयूई) में धीरे-धीरे आई कमी के कारण एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है, जिसमें किसान रासायनिक खादों की मात्रा तो लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादकता में बहुत मामूली बढ़ोतरी ही हो रही है।

सरकार की मृदा स्वाथ्य और उर्वरक योजना के तहत 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण किया गया है। इससे प्राप्त डेटा के अखिल-इंडिया विश्लेषण से चिंताजनक बात सामने आई है कि मिट्टी में जैविक कार्बन (एसओसी) और अन्य जरूरी सूक्ष्म-पोषक तत्वों की भारी कमी है। स्वस्थ मिट्टी में एसओसी 1त्न से अधिक होना चाहिए, लेकिन यह औसतन 0.5त्न के आसपास है और कुछ क्षेत्रों में यह 0.3त्न तक के यह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।

कम मात्रा में एसओसी से मिट्टी की सरंध्रता कम हो जाती है, जिसका दोहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैः पानी का जमीन में रिसाव और जल धारण क्षमता, दोनों में कमी आती है। परिणामस्वरूप, वर्षा और सिंचाई का पानी बह जाता है, जो ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है और न तो यह जमीन के नीचे जाकर भूजल स्तर बढ़ा पाता है और न ही पौधों की वृद्धि के लिए आसानी से उपलब्ध रहता है।

कम एसओसी का एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि ऐसे मिट्टी पर उगाए जाने वाले पौधों की पोषक तत्व अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। समान उत्पादकता स्तर तक पहुँचने के लिए अधिक से अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई खुराक उर्वरक उपयोग दक्षता को और कम कर देती है, जिससे मृदा-स्वास्थ्य का नुकसान होता है और देश रासायनिक उर्वरकों या उनके घरेलू उत्पादन के कच्चे माल को आयात करने में अपनी कीमती विदेशी मुद्रा खर्च करता है।

अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के असंतुलित उपयोग ने उन लाभकारी सूक्ष्मजीवों और कीड़ों को भी कम कर दिया है, जो मिट्टी की सरंध्रता को बेहतर बनाने और गहरी मिट्टी से पोषक तत्वों को ऊपरी मिट्टी तक स्थानांतरित करने में मदद करते हैं, ताकि पौधे उन्हें अवशोषित कर सकें।

एक अन्य चिंताजनक प्रभाव उपज की गुणवत्ता और सुरक्षा पर पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि रसायन खाने-पीने और पशु चारे की श्रृंखला में पहुँच जायेंगे और आखिरकार मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करेंगे। ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें फलों, सब्जियों, अनाज और अन्य वाणिज्यिक फसलों में कीटनाशकों का न्यूनतम अवशेष स्तर तय सीमा को पार कर गया है, जिसके चलते निर्यात की खेपें रद्द होती हैं और वैश्विक बाजार में ब्रांड इंडिया की छवि पर बुरा पड़ता है।

हालांकि ये चिंताएँ कुछ समय से व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन सरकार ने वर्ष 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत कृषि के लिए पशुधन या गाय आधारित रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है, ताकि मिट्टी की सेहत खासकर एसओसी में सुधार हो सके, पौष्टिक तत्वों के अवशोषण की क्षमता बढ़ सके और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर देश की निर्भरता कम हो सके।

प्राकृतिक खेती, जिसे इसके समर्थकों द्वारा आमतौर पर 'जीरो बजट खेती' कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक पर आधारित है, जिसे किसानों ने कई सालों तक आज़माया और परखा है तथा इसे मान्यता दी है। इसके परिणाम भी बहुत उत्साहजनक रहे हैं। यह एक समग्र तकनीकी समाधान पर आधारित है, जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे स्थानीय नस्ल की गाय का गोबर और गोमूत्र, जिनकी लागत किसान के लिए लगभग शून्य होती है।

बीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाला बीजामृत सूत्र बेहतर अंकुरण और मजबूत पौधों में मदद करता है, जबकि जीवामृत, घन-जीवामृत और सप्तयांकुर का उपचार मित्र सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी और मृदा-उत्पादकता को काफी बढ़ा देता है। पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा सौंठास्त्र और खट्टी लस्सी के इस्तेमाल से की जाती है, जो बैक्टीरिया और फफूंद संक्रमण को रोकते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के कीड़ों और कीट को नियंत्रित करने के लिए 'नीमास्त्र', 'ब्रह्मास्त्र', 'अग्निअस्त्र' और 'दशपर्णी अर्क' का प्रयोग किया जाता है।

उपरोक्त सभी उपचारों की सावधानीपूर्वक तैयारी और उचित मात्रा में उपयोग से मिट्टी की सेहत के बेहतर परिणाम मिले हैं और उत्पादकता पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि उपज की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

मिशन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से प्रगति कर रहा है, जिसका लक्षित क्षेत्र 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक है और यह 18 लाख से अधिक किसानों को कम से कम 50 हेक्टेयर के क्लस्टर में कवर करता है। कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की टीम, जिसे किसान प्रशिक्षक और कृषि सखी संसाधन व्यक्ति के रूप में सहायता प्रदान कर रहे हैं, किसानो को जागरूक कर रही है, प्रशिक्षण दे रही है और इस खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

जिन किसानों के पास स्थानीय नस्ल की गायें हैं, उन्हें खेत पर ही इन उपचारों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, बड़ी संख्या में जैव-इनपुट संसाधन केंद्र भी मुख्य रूप से स्थानीय डेयरियों या पशु आश्रय गृहों के निकट स्थापित किए गए हैं, ताकि ये उपचार किसानों को मामूली कीमत पर उपलब्ध कराए जा सकें।

यह मिशन विज्ञान-आधारित रणनीति के माध्यम से लागू किया जा रहा है, ताकि किसान इन प्रथाओं को बिना किसी संदेह या हिचकिचाहट के अपना सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने क्षेत्र और फ़सल-विशिष्ट क्षमता मानचित्र विकसित किए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्राकृतिक खेती कहाँ प्रभावी होगी। आईसीएआर के संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में इस देसी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए इसकी प्रभावशीलता को वैज्ञानिक रूप से मान्यता देने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। आईसीएआर संस्थानों की निगरानी में किए गए कई प्रयोगों ने कई फसलों के लिए बहुत सकारात्मक परिणाम दिए हैं और अब मिशन के ज़रिए इनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

प्राकृतिक उत्पादों का विपणन एक और महत्वपूर्ण रणनीति है, जो किसानों की आय में वृद्धि करेगी और उन्हें इन प्रथाओं को जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी। राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र (एनसीओएनएफ) ने प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणीकरण नियम बनाये हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने पहले ही सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं, जिससे वे अपने प्रमाणित विशिष्ट उत्पाद को ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं।

एक तरफ जहां इस मिशन के तहत प्रमाणन, विपणन और ब्रांडिंग के साथ शुद्ध प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक हाइब्रिड मॉडल को प्रोत्साहन देने की रणनीति में यह दिखाया गया है कि प्राकृतिक खेती की प्रथाओं को अपनाने और रासायनिक उर्वरकों की खुराक को कम करने से भी लंबे समय तक उत्पादकता बनी रह सकती है और मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इस मॉडल को व्यापक स्वीकार्यता मिल सकती है। इसे अपनाने वाले किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाइब्रिड मॉडल में प्राकृतिक खेती की प्रथाओं को अपनाने से रासायनिक उर्वरकों पर धीरे-धीरे निर्भरता कम होती है। यहाँ तक कि कुछ समय बाद, किसान कई फसलों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर सकते हैं और फिर भी उतनी ही पैदावार और आमदनी बनाए रख सकते हैं।

मध्य पूर्व में चल रहे मौजूदा संकट से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से सात सूत्रीय अपील की है, जिनमें रासायनिक खाद का समझदारी से इस्तेमाल और प्राकृतिक खेती को अपनाना शामिल हैं।

एक ओर जहाँ प्राकृतिक खेती को अपनाने से खेती में स्थायित्व आ रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे पशुधन के आर्थिक मूल्य को बढ़ाने में भी मदद मिल रही है, जिनका आम तौर पर दूध देने की उम्र खत्म होने के बाद परित्याग कर दिया जाता है। इसका एक और फ़ायदा यह है कि घरेलु उपभोग और निर्यात के लिए सुरक्षित भोजन मिलता है, साथ ही देश की कीमती विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है।

(लेखक भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं)

बीकेयू नेताओं से क्रूरता: 'एक गोली मुझे मारो, फिर इनका एनकाउंटर'

एसएसपी ने कही थी ये बात, स्कूटी से गिरने की कहानी

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ में भाकियू नेताओं से क्रूरता का मामला सामने आया है। किसान नेताओं ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एसएसपी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर बेरहमी से पीटा गया। इसके अलावा थाने के अंदर गानों पर नचवाया गया। सपा विधायक अतुल प्रधान के आवास पर शुक्रवार को पत्रकारों के सामने आंख, हाथों की उंगलियां और पैरों पर चोट के नीले निशान दिखाकर भाकियू (बीआर आंबेडकर) के अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव फूट-फूटकर रो पड़े।

दोनों किसान नेताओं ने दो दिन पहले एसएसपी कार्यालय में पुलिस की ओर से किए गए अमानवीय बर्ताव की विस्तार से जानकारी दी। बताया कि एसएसपी और इंस्पेक्टर सिविल

लाइन अखिलेश गौड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटा।

बर्बरता की हद पार करते हुए आंखों पर बूट से प्रहार किया। इससे आंख पर गंभीर चोटें आई और दांत तक टूट गए। दावा किया कि पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाह रही थी। शुक्रवार को रो-रोकर दिग्विजय भाटी ने पुलिस की बेरहम पिटाई से अपने शरीर पर हुए घाव दिखाए।

बताया कि 19 अगस्त को वह अपने जिलाध्यक्ष मोहित जाटव के साथ एसएसपी अविनाश पांडेय से मिलने गए थे। ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़े विरोध-प्रदर्शन मामले में पुलिस ने हम 8-10 लोगों को जेल भेज दिया था। जबकि, हमारी कोई गलती नहीं थी। न ही हम प्रदर्शन में शामिल थे। इसलिए हम कप्तान को सच बताने गए थे।

दिग्विजय भाटी ने कहा कि पुलिसवालों ने बर्बरता की सभी हदें पार कर दीं। पुलिस वालों ने पहले तो हमें पीट-पीटकर अधमरा किया, इसके बाद मोबाइल पर खलनायक फिल्म का गाना बजाकर हमें बार-बार नचवाते रहे। सरधना के सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि जो बर्बरता एसएसपी और सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने की वह चिंताजनक है। सरकार को पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए।

इंस्पेक्टर ने खलनायक फिल्म के गाने पर डांस करवाया

सपा विधायक अतुल प्रधान के आवास पर प्रेसवार्ता में दिग्विजय भाटी ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए। भाटी ने बताया कि पहले उन्हें और मोहित जाटव को एसएसपी दफ्तर में पीटा गया, उसके बाद सिविल लाइंस थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ को बुलाया गया। भाटी ने बताया कि कप्तान के ऑफिस से सिविल लाइन थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ उन दोनों को एसओजी दफ्तर ले गए। वहां जाकर दोनों से एक-दूसरे के हाथ-पैर बंधवाए गए।

बुरी तरह पीटने के बाद कहा गया कि अब डांस करना है। फिर इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ ने मोबाइल पर खलनायक फिल्म का गाना- चोली के पीछे क्या है बजाया और पहले भाटी को नचवाया। इसके बाद मोहित जाटव से कहा कि दोनों गाना गाओ और नाचो। मोहित ने बताया कि बुरी तरह पीटे जाने के बाद वह दोनों सिर्फ हाथ भर हिला पा रहे थे। कुछ देर बाद वह बोले कि उन्हें नींद की झपकी लग गई थी। अब दोबारा नाचो। वह उन पर सिर पर कपड़ा डालकर नाचने का भी दबाव बना रहे थे। इस बार छत पर सोया था बहनोई... फिल्मी गीत चलवाया और नाचने के लिए कहा।

दिग्विजय का दावा है कि एसएसपी उनके एनकाउंटर की योजना बना चुके थे। एसएसपी ने पुलिसवालों से कहा था कि एक गोली मुझे मारो और फिर इनका एनकाउंटर कर दो। मैं सब देख लूंगा। हाथों की उंगलियों पर लाठी मारते रहे। कहते रहे कि इन हाथों से चार दिन भी रोटी नहीं खा पाओगे। जैसे तैसे सरधना विधायक अतुल प्रधान छुड़ाकर लाए।

दिग्विजय भाटी ने रोते हुए बताया कि आठ जुलाई के प्रदर्शन में हम लोग शामिल नहीं थे, फिर भी हमें टारगेट किया गया। एक गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए थे। ऐसा ही अगर होता रहा तो कोई भी किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। मोहित जाटव का कहना था कि वह अपने समाज के नेता हैं। ऑफिस जाने से पहले उनकी पुलिस अफसर से फोन पर बात हुई थी। जिस तरह का व्यवहार फोन पर था, उस तरह का व्यवहार सामने बिल्कुल नहीं था। दरअसल इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने बचने का रास्ता खोजने के लिए पहले ही नई कहानी रच ली थी। पिटाई का मामला तूल पकड़ने पर मेरठ पुलिस ने एक्स पर दिग्विजय भाटी और मोहित का आपराधिक इतिहास शेयर कर दिया। दोनों के वायरल वीडियो का जवाब देते हुए मेरठ पुलिस के एक्स हैंडल पर लिखा कि दिग्विजय भाटी और मोहित अपने-अपने थानों के हिस्ट्रीशीटर हैं। दिग्विजय भाटी पर 10 और मोहित पर सात मामले दर्ज हैं। उनकी ओर से पुलिस पर लगाए गए आरोप असत्य और निराधार हैं। दोनों लोगों को स्कूटी से फिसल कर चोटिल होना बता दिया गया।

मेरठ पुलिस ने एक्स हैंडल पर लिखा कि संभल के चमरौआ गांव निवासी दिग्विजय सिंह भाटी और भावनपुर थाना क्षेत्र के किनानगर गांव निवासी मोहित के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं। बुधवार को दोनों सिविल लाइन थाने पर दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में वार्ता करने आए थे। यहां से वापस घर जाते समय स्कूटी फिसलने से दोनों गिरकर चोटिल हो गए थे। इस संबंध में दिग्विजय सिंह एवं मोहित ने स्वयं थाना सिविल लाइन पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। इसका जीडी संख्या-53, समय 17:31 बजे पर अंकित किया गया है। हालांकि शुक्रवार को दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने साफ कर दिया कि उनसे जबरिया कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे।

हत्याकाण्ड में सांसद प्रतिनिधि सहित चार दोषी करार

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। करीब 22 साल पुराने बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज मौर्या समेत चार सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे/एफटीसी प्रथम की अदालत ने चारों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। वहीं, मामले में दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत अब 26 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।मामला वर्ष 2004 का है। 16 अगस्त 2004 को लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियापुर मोहल्ले में कलेक्ट्रेट तिराहे के पास जमीनी विवाद को लेकर दिनदहाड़े आशीष मौर्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले में लाइन बाजार थाने में सात आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, मामले में राम सेवक मौर्या, अश्वनी मौर्या, आशीष मौर्या, पवन मौर्या, मनोज मौर्या समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आखिरकार अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। इस हत्याकांड में लंबे समय तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद एडीजेध्एफटीसी प्रथम की अदालत ने चार सगे भाइयों को हत्या के मामले में दोषी माना। फैसला आते ही अदालत परिसर में हलचल बढ़ गई। दोषी ठहराए गए चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। अदालत द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें 26 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन अदालत में दोषियों को दी जाने वाली सजा के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस होगी।

गंगा का रौद्र रूप! बिजनौर बैराज का तटबंध टूटा, 100 मीटर कंक्रीट ब्लॉक नदी में समाया

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है। गंगा के बढ़े जलस्तर और तेज बहाव ने बिजनौर में गंगा बैराज के लेफ्ट अफलैक्स बंध (बाएं तटबंध) को भारी नुकसान पहुंचाया है। नदी की तेज जलधारा सीधे इस बंध से टकरा रही है, जिसके कारण आर्टिकुलेटेड कंक्रीट ब्लॉक मेट्रेस (ACBM) का 1060 मीटर में से करीब 100 मीटर का हिस्सा धंस गया है।

इस अचानक आई आपदा ने सिंचाई विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। गंगा बैराज के रावली स्थित लेफ्ट अफलैक्स बंध नदी के पानी को आबादी और कृषि भूमि की तरफ जाने से रोकता है। पिछले कुछ दिनों से गंगा का रुख इस बाएं तटबंध की तरफ सीधा हो गया है। नदी की लहरों की सीधी और तीव्र टक्कर के कारण तटबंध की सुरक्षा के लिए बिछाए गए 1060 मीटर क्षेत्र में

एसीबीएम कंक्रीट ब्लाक का करीब 100 मीटर का पैच नदी में समा गया।

सिंचाई विभाग में मचा हड़कंप, राहत कार्य शुरू

मध्य गंगा नहर निर्माण खंड पांच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर्णपाल सिंह ने बताया कि एसीबीएम कार्य करने वाली फर्म के स्टाफ को बुलवाकर क्षतिग्रस्त क्षेत्र पर सुरक्षात्मक कार्य कराए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग के बंध धंसने की सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों की टीम में हड़कंप मच गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत मौके का निरीक्षण किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कटान प्रभावित हिस्से पर युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

मध्य गंगा के चीफ इंजीनियर कृष्ण मोहन कंसल, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीव झा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर्णपाल सिंह सिंचाई विभाग की पूरी टीम के साथ तटबंध को सुरक्षित बचाने के लिए पिछले तीन दिनों से तटबंध पर ही डेरा डाले हुए हैं। प्रभावित क्षेत्र में टेट्राहेड्रोन पोरक्युपाइन, पत्थरों से भरे वायर क्रेट (तार के जाल) डाले जा रहे हैं, ताकि पानी के सीधे वेग को कम किया जा सके। कटान को रोकने के लिए हजारों की संख्या में रेतीली बोरियों को धंसे हुए पैच पर लगाया जा रहा है।

क्या बोले इंजीनियर इन चीफ?

यूपी सिचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ अवधेश कुमार ने बताया कि गंगा नदी की धारा लेफ्ट अफलैक्स बंध पर सीधी टक्कर मार रही है, खतरे की कोई बात नहीं है। तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है उसको तेजी से मजबूत करने के साथ-साथ विभागीय इंजीनियर्स की टीमों को रात दिन सतर्क रह कर तटबंध की निगरानी के आदेश दे दिए गए हैं।

विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही योगी सरकार

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में अवस्थापना निधि के अंतर्गत विकास कार्य का शनिवार को शिलान्यास किया गया। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव ने विकास भवन से जिला पंचायत कार्यालय तक 250 मीटर इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस विकास कार्य पर 53.12 लाख रुपये की लागत आएगी। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में आवागमन सुगम होने के साथ ही जल निकासी की व्यवस्था भी बेहतर होगी। शिलान्यास के दौरान राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शहरों और सरकारी परिसरों में बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि जौनपुर में भी

सड़क, नाली, जल निकासी सहित आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में होने वाला यह कार्य कर्मचारियों, अधिकारियों और यहां आने वाले आम लोगों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराकर आम जनता को उसका सीधा लाभ पहुंचाना है। कलेक्ट्रेट परिसर में इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण से जलभराव की समस्या कम होने के साथ परिसर की व्यवस्था भी बेहतर होगी।

मातमी सदाओं से गूंजा शहर, निकला चुप ताजिया

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। अय्यामे अजा के आखिरी दिन शनिवार को शहर के विभिन्न इमामबाड़ों से मातमी जुलूस निकाले गए। अंजुमनों ने नौहाख्वानी और सीनाजनी कर इमाम हसन अस्करी व शोहदाए करबला को नजरान-ए-अकीदत पेश किया। जुलूस में बड़ी संख्या में अजादार शामिल हुए।मोहल्ला सिपाह स्थित अजाखाना मरहूम सैयद हैदर मेंहदी में मजलिस-ए-अजा आयोजित हुई। मजलिस का आगाज सोजख्वानी से हुआ। गौहर अली जैदी व उनके हमनवाओं ने सोजख्वानी पेश की। इसके बाद मौलाना फजले मुमताज ने मजलिस को खिताब करते हुए इमाम हसन अस्करी की शहादत और शोहदाए करबला के मसायब बयान किए। मसायब सुनकर अजादारों की आंखें नम हो गईं। मजलिस के बाद

इमाम हसन अस्करी के शबीहे ताबूत के साथ अलम, जुल्जनाह व अमारियां बरामद हुईं। अंजुमन मासूमिया के अजादार नौहाख्वानी और सीनाजनी करते हुए कदीमी रास्तों से इमामबाड़ा नबी साहब स्थित कर्बला पहुंचे, जहां शबीह को ठंडा किया गया। अजाखाना शहंशाह हुसैन से भी मातमी जुलूस निकाला गया। इसमें अंजुमन अजाए अहलेबैत और अंजुमन गुलशने इस्लाम बाजारभुआ के अजादार शामिल हुए। जुलूस में शबीहे अलम, शबीहे जुल्जनाह, ताबूत इमाम हसन अस्करी और शबीहे ताबूत जनाबे सकीना (स.अ.) बरामद हुआ। अंजुमनों ने नौहाख्वानी व सीनाजनी करते हुए कदीमी रास्तों से गुजरकर इमामबाड़ा नबी साहब पहुंचकर जुलूस का समापन किया। अय्यामे अजा के समापन के साथ ही मोहर्रम के दो महीने और आठ दिन की अजादारी का सिलसिला भी पूरा हो गया। इससे पूर्व शुक्रवार की रात शहर के विभिन्न इमामबाड़ों में देर रात तक नौहाख्वानी और सीनाजनी का दौर चलता रहा। कई इमाम चैकों पर ताजिए रखे गए, जहां अकीदतमंदों ने नौहाख्वानी के बीच अश्कों का नजराना पेश किया।

धमाके के साथ बंद हुई लिफ्ट, चीखती रही मासूम... मुरादाबाद की हाईराइज सोसाइटी में बड़ी लापरवाही

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पॉश ग्रीन ऑर्किड सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा होते-होते बचा। यहां स्कूल से वापस लौटी चौथी कक्षा की आठ वर्षीय मासूम छात्रा कीर्ति शुक्ला करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। घटना के समय बच्ची अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से घर आ रही थी। तीसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट तक जाने के लिए छोटे भाई ने सीढ़ियों का रास्ता चुना, जबकि छात्रा ने लिफ्ट का इस्तेमाल किया। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक दूसरे फ्लोर पर एक जोरदार धमाके और तेज आवाज के साथ ठप्प हो गई।

उसके भारी दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो गए। लिफ्ट के भीतर फैले अंधेरे और घुटन से घबराई मासूम ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान

बचाने के लिए पूरी ताकत से मदद के लिए चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे उसके भाई ने जैसे ही बहन की घबराई हुई चीख सुनी, वह भागकर तुरंत ऊपर गया और परिजनों को घटना की सूचना दी। बदहवास परिजन तत्काल नीचे दौड़े और मुख्य सुरक्षा गार्ड को मौके पर बुलाया, लेकिन तकनीकी खराबी इतनी गंभीर थी कि चाबी लगाने के बावजूद लिफ्ट का मुख्य दरवाजा टस से मस नहीं हुआ, जिससे मौके पर अफरातफरी और तनाव का माहौल बन गया।

बच्ची रो-रोकर हो रही थी बदहवास

लिफ्ट का दरवाजा चाबी से भी न खुलने के कारण मौके पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। मासूम बच्ची अंदर घुटन और डर के मारे बुरी तरह रो-रोकर बदहवास हो रही थी। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सुरक्षा गार्ड ने सूझबूझ से काम लिया और लिफ्ट के अंदर फंसी बच्ची को कहा वह हिम्मत जुटाकर अपने दोनों हाथों से दरवाजे के किनारों को अंदर की तरफ से पकड़कर पूरी ताकत से बाहर खींचने की कोशिश करे। मासूम बच्ची ने डर के बावजूद गार्ड के निर्देशों का पालन किया और अंदर से दरवाजे को खींचना शुरू किया।

करीब 15 मिनट की मशक्कत और कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा सा खुला, जिसके बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इस भयावह हादसे से उबरने के बाद छात्रा कीर्ति शुक्ला ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि लिफ्ट अचानक बड़े धमाके के साथ रुक गई थी और जब चाबी से भी गेट नहीं खुला तो वह पूरी तरह घबरा गई थी।

सोसाइटी के निवासियों में भारी आक्रोश

वहीं इस घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में बिल्डर और रखरखाव टीम की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश फैल गया है। लोगों का आरोप है कि ग्रीन ऑर्किड सोसाइटी में 15 दिन पहले भी एक महिला अपने मासूम बच्चे के साथ इसी तरह लिफ्ट में फंसी रही थी। बार-बार शिकायतों के बावजूद बिल्डर द्वारा लिफ्ट की समय पर मेंटेनेंस और सर्विसिंग नहीं कराई जा रही है, जिससे बहुमंजिला इमारत में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

करोड़ों की जमीन और डीआरडीओ अफसर से शादी... वाराणसी के श्रेया मर्डर केस की इंसाइड स्टोरी, आरोपी अभी भी फरार

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी के मरुई गांव की होनहार छात्रा श्रेया उपाध्याय हत्याकांड को 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं। Msc की पढ़ाई के साथ नीट (NEET) की तैयारी कर रही श्रेया की बच्छांव स्थित एक कमरे के बाथरूम में बेहद बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की चार-चार टीमें गठित होने के बावजूद मुख्य आरोपी विवेक चौबे अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। श्रेया के चचेरे भाई अंशुमन उपाध्याय ने हत्याकांड की वजह का खुलासा करते हुए बताया कि श्रेया अपने पिता सुनील उपाध्याय की इकलौती बेटी थी और उसके नाम पर करोड़ों रुपये की पारिवारिक संपत्ति है।

श्रेया नीट की तैयारी के लिए फार्मेसी पढ़े विवेक चौबे से पढ़ाई में

मदद लेती थी और उसे अपना भाई मानती थी। लेकिन विवेक उस पर बुरी नजर रखता था। श्रेया की शादी हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के एक अधिकारी से तय हुई थी। नवंबर में सगाई और फरवरी में शादी होनी थी। शादी तय होते ही विवेक को लगा कि इकलौती बेटी की शादी के बाद करोड़ों की जमीन और संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। इसी लालच और खुन्नस में उसने श्रेया की नृशंस हत्या कर दी।

श्रेया 18 अगस्त को जगतपुर पीजी कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। जक्खनी पुलिस 18 अगस्त को ही मोबाइल लोकेशन के आधार पर बच्छांव स्थित कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन ताला बंद होने और कोर्ट का आदेश न होने का हवाला देकर पुलिस बिना ताला तोड़े लौट गई। 19 अगस्त को जब विवेक के मामा कमरे की चाबी लेकर पहुंचे और दरवाजा खोला गया, तो अंदर बाथरूम में श्रेया का गला कटा हुआ शव बेहद बुरी हालत में मिला। परिजनों ने विवेक के मामा की भूमिका पर भी गहरा संदेह जताया है।

आरोपी के एनकाउंटर की मांग, पुलिस का दावा

रोते-बिलखते पिता सुनील उपाध्याय और चचेरे भाई अंशुमन ने आरोपी विवेक चौबे को कड़ी से कड़ी सजा और एनकाउंटर की मांग की है। मामले में DCP क्राइम/गोमती नीतू कादयान ने बताया- आरोपी विवेक चौबे की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है और आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

उप परिवहन आयुक्त ने किया रिश्वत मांगने की जांच

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। एआरटीओ कार्यालय में कथित घूसखोरी की शिकायत की जांच के लिए शनिवार को उप परिवहन आयुक्त भीमसेन सिंह और एआरटीओ प्रशासन राघवेंद्र सिंह पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान उप परिवहन आयुक्त ने रजिस्ट्रेशन पटल पर तैनात बाबू गणेशदत्त को वहां से हटा दिया। उन्हें अब डिस्पैच पटल का कार्यभार सौंपा गया है। उप परिवहन आयुक्त भीमसेन सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आवश्यक लिखापढ़ी करने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता मडियाहूं निवासी विनय सिंह ने बाबू को केवल पटल से हटाए जाने की कार्रवाई पर

असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि यदि गणेशदत्त के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो मंगलवार तक धरने पर बैठेंगे। विनय सिंह ने आरोप लगाया कि जिले के कई मोटर मालिक कथित घूसखोरी से परेशान हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे मामला सामने आया था। वाहन मालिक विनय सिंह अपने पांच ट्रकों को लेकर एआरटीओ कार्यालय पहुंच गए और उन्हें कार्यालय के सामने खड़ा कर दिया।एक साथ पांच ट्रकों के खड़े होने से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। विनय सिंह ने रजिस्ट्रेशन बाबू गणेशदत्त पर पांचों ट्रकों के रजिस्ट्रेशन के लिए कथित तौर पर 50 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। विनय सिंह के मुताबिक, उन्होंने पांचों ट्रकों के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे। इसके बावजूद करीब एक सप्ताह तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उनका आरोप था कि रिश्वत देने से इनकार करने पर फाइल को लगातार टाला जा रहा था।

ऐसी जगह जहां पांव रखने पर हिलती महसूस होती है जमीन

आपने गांव तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आप भारत को उस अनोखे और इकलौते तैरते हुए गांव के बारे में जानते हैं, जो झील में बसा है। हम कश्मीर की डल झील की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह गांव एक दूसरे राज्य में है। उस गांव के लोग 250 किमी में फैली झील में तैरती मोटी घासों के ऊपर बने हैं।

आपने बोट पर बने घर देखे होंगे जो पानी पर तैरते हैं। हालांकि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो देखने में जमीन जैसी लगती है, लेकिन असल में ये ठोस जमीन नहीं होती है। ये जगह भारत के मणिपुर राज्य में है। ये जमीन फुमदी कहलाती है, जो पानी के ऊपर मिट्टी और घास, झाड़ियों के सड़ने से होने वाले जमाव से बनकर तैयार होती है। ये इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि लोग इसके ऊपर अपने घर बनाकर रहते हैं। यहां के लोग झील में ही नाव से आना-जाना करते हैं और मछली पालन यहां का मुख्य व्यवसाय है।

ये फुमदियां झील का पानी बढ़ने या घटने पर छोटी या बड़ी हो जाती हैं। इसी के साथ हवा और पानी के बहाव की वजह से ये धीरे-धीरे अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती हैं, जिससे लोगों के आशियाने भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। चलिए जान लेते हैं इस अनोखी जगह के बारे में और आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं।

क्या है इस गांव का नाम?

मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित इस गांव का नाम चंपू खंगपोक है, जिसे फ्लोटिंग विलेज यानी तैरता हुआ गांव भी कहते हैं। फुमदी यानी गली-सड़ी हुआ वनस्पतियों, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों से बने हुए बड़े-बड़े ढेले या जमीन जैसे टुकड़े होते हैं जो झील के पानी पर तैरते हैं। इस झील का नाम है 'लोकतक'। इस स्पंजी सी महसूस होने वाली जगह पर लोग बांस की झोपड़ियां बनाते हैं।

स्कूल से लेकर हैं कई सुविधाएं

चंपू खंगपोक गांव में लोगों ने खुद को इसी एनवायरमेंट के हिसाब से ढाल लिया है। यहां पर मुख्यतः मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मुख्य रूप से जीवन यापन के लिए ज्यादातर लोग यहां पर मिलने वाली नेचुरल चीजों और मछली पकड़ने के काम को करते हैं। यहां सिर्फ घर ही नहीं हैं, बल्कि बच्चों के लिए स्कूल भी बना हुआ है और कम्युनिटी हॉल भी है जहां लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर सामाजिक चर्चाओं के लिए बैठक तक करते हैं। यहां के लोग लकड़ी की डोंगी से ही अलग-अलग जगहों पर पहुंचते हैं। अब यहां सोलर लाइट जैसी सुविधाएं भी पहुंच गई हैं।

तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान

यहां पर आना इसलिए भी खास रहेगा, क्योंकि आप एक अनोखी दुनिया में पहुंचने जैसा महसूस करेंगे और वहां की अनूठी संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा लोकतक झील पर ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान (कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क) भी है जो दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है। यह खासतौर पर 'संगई' (डान्सिंग डियर) भी देखने को मिलेंगे जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं।

कैसे पहुंचें चंपू खंगपोक?

इस गांव में आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर में माना जाता है, क्योंकि मानसून खत्म हो चुका होता है और पानी थोड़ा कम हो जाता है। इसी के साथ हरियाली भी पीक पर रहती है। यहां पहुंचने के लिए फ्लाइट से आप बीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतर सकते हैं। ट्रेन से आपको दीमापुर उतरना होगा। आपको इन जगहों से प्राइवेट या शेयर्ड टैक्सी लेनी होंगी जो झील के किनारे बसे मोइरांग या फिर थांगा तक पहुंचा जेती हैं। इसके बाद आप पारंपरिक नाव से चंपी खंगपोक जा सकते हैं।

मछली पकड़कर चलाते हैं अपना गुजारा

इस गांव के रहने वाले लोगों का मुख्य धंधा मछली पकड़ना है। वे झील में गोलाकार मछली पकड़ने वाले घेरे बनाते हैं। इसके बाद बड़े आकार की मछलियों को पकड़कर नाव के जरिए पास के बाजारों में बेचने जाते हैं और वहां से लौटते हुए अपने जरूरत की चीजें खरीदकर ले आते हैं। इस गांव में एक फ्लोटिंग स्कूल और कम्युनिटी हॉल भी है।

250 वर्ग किमी में फैली है झील

हम भारत के जिस इकलौते तैरते हुए गांव की बात कर रहे हैं। उसका नाम चंपू खंगपोक (Champu Khangpok) है। यह गांव मणिपुर की लोकटक झील में बसा है। इसे दुनिया का अनोखा तैरता हुआ गांव माना जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल घाटी के अंदर यह लोकतक झील (Loktak Lake) है। करीब 250 वर्ग किमी में फैली यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मानसून के दौरान पानी बढ़ने की वजह से इस झील का एरिया फैलकर करीब 500 वर्ग किमी तक हो जाता है।

दुनिया का तैरता हुआ इकलौता गांव

खास बात ये है कि यह भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का तैरता हुआ अनोखा गांव है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कश्मीर की डल झील में बसे किसी गांव की बात कर रहे हैं तो आपका अनुमान गलत है। इस खूबसूरत गांव के बारे में देश के 99 फीसदी लोगों के बारे में सुना तक नहीं होगा। आइए हम आपको इस दिलचस्प गांव की यात्रा पर लिए चलते हैं और बताते हैं कि यह अनोखा गांव कहां है।

दुनिया में तैरता हुआ नेशनल पार्क

इसी झील में केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। यह दुनिया में तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है, जो इसी झील की सबसे बड़े फुमदी पर है। इस नेशनल पार्क में लुप्तप्राय सांगाई हिरण पाया जाता है। यह झील लोगों को सिंचाई, मछली, पीने का पानी और आजीविका प्रदान करती है, इसलिए इसे मणिपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अगर आप कभी मणिपुर घूमने जाएं तो इस झील और लोकतक गांव का भ्रमण करना न भूलें। यह आपके जीवन का ऐसा अविस्मरणीय अनुभव होगा, जो आपको जीवनभर याद रहेगा।

क्या अच्छी नींद सच में स्किन की सेहत सुधारने में मदद कर सकती है?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। ऐसे में क्या नींद की कमी का असर हमारी स्किन पर भी पड़ सकता है? आइए जानते हैं।

नींद शरीर और दिमाग को आराम देने के साथ कई जरूरी प्रक्रियाओं के लिए भी अहम होती है। दिनभर की थकान और तनाव के बाद शरीर को खुद को संभालने के लिए पर्याप्त नींद की जरूरत होती है। नींद पूरी न होने पर थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान लगाने में परेशानी और दिनभर सुस्ती महसूस हो सकती है। लंबे समय तक नींद की कमी रहने पर इसका असर ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ सकता है।

ऐसे में नींद का असर त्वचा की सेहत पर भी पड़ सकता है। अच्छी और पर्याप्त नींद लेने से स्किन की हेल्थ बेहतर रखने में मदद मिल सकती है, जबकि लगातार कम नींद लेने पर त्वचा थकी और बेजान दिख सकती है। आंखों के नीचे काले घेरे और सूजन जैसी परेशानियां भी नजर आ सकती हैं। आइए जानते हैं अच्छी नींद कैसे त्वचा की सेहत को बेहतर बनाती है और इससे स्किन को क्या फायदे मिल सकते हैं।

Healthline के मुताबिक, सोते समय शरीर आराम करने के साथ त्वचा की मरम्मत का काम भी करता है। नींद के दौरान त्वचा में ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, जिससे त्वचा तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचने में मदद मिलती है। इससे त्वचा को खुद को रिपेयर करने में मदद मिल सकती है। इसी दौरान शरीर कोलेजन भी बनाता है, जो त्वचा को मजबूत और लचीला रखने में मदद करता है।

अच्छी नींद से चेहरे की त्वचा ज्यादा फ्रेश और हेल्दी दिखाई दे सकती है। पर्याप्त नींद त्वचा को धूप और दिनभर के दूसरे नुकसान से उबरने में भी मदद कर सकती है। इसके अलावा, अच्छी नींद तनाव को कम रखने में मदद करती है और तनाव कम होने से त्वचा पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। हालांकि, सिर्फ अच्छी नींद लेने से त्वचा की हर समस्या ठीक नहीं होती। स्किन हेल्थ के लिए खानपान, पानी और स्किन केयर भी जरूरी हैं।

कम नींद लेने से स्किन पर क्या असर पड़ता है?

नींद की कमी से आंखों के नीचे काले घेरे और सूजन ज्यादा नजर आ सकती है। इसका असर त्वचा की रंगत पर भी पड़ सकता है और चेहरा कम फ्रेश दिखाई दे सकता है। कम नींद शरीर के तनाव को बढ़ा सकती है, जिसका असर कुछ लोगों में स्किन पर भी दिख सकता है।

लंबे समय तक नींद पूरी न होने से त्वचा की खुद को रिपेयर करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों में इससे झुर्रियां ज्यादा दिखाई देने लग सकती हैं।

स्किन की सेहत के लिए कितनी नींद लेना जरूरी है?

स्किन और पूरी सेहत के लिए रोज पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। आमतौर पर एक स्वस्थ एडल्ट को 7 से 9 घंटे की नींद लेने की सलाह दी जाती है। सिर्फ एक-दो दिन कम सोने से ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक नींद पूरी न होने पर इसका असर शरीर और त्वचा दोनों पर पड़ सकता है। बेहतर नींद के लिए सोने और जागने का समय तय रखें, रात में मोबाइल और दूसरी स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और सोने से पहले कैफीन लेने से बचें।

दर्द कम करने के लिए किचन की ये चीजें करें यूज, इमरजेंसी में आती हैं काम

भारतीय रसोई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमरजेंसी में दवा न होने पर आपके काम आ सकती हैं। दादी-नानी पुराने समय से इन चीजों का इस्तेमाल देसी नुस्खों में करती आ रही हैं, इसलिए इससे नुकसान होने की संभावना भी बहुत कम होती है। पेट दर्द से लेकर दांत दर्द से राहत पाना हो तो टेबलेट खाने की बजाय कुछ नेचुरल चीजें भी काम आ सकती हैं। दरअसल बार-बार पेन किलर टेबलेट लेना भी सेहत के लिए सही नहीं माना जाता है, ऐसे में रसोई में छुपी दर्द निवारक चीजें आपके काम आ सकती हैं। चलिए डिटेल में जान लेते हैं।

आपको हाथ-पैर या शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाती है तो हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है। इसके अलावा सूजन और दर्द हो तो भी आप बस हल्दी को सरसों के तेल में गर्म कीजिए और इसे प्रभावित जगह पर लगाकर पट्टी बांध दें। इससे काफी आराम मिलता है। हल्दी वाला दूध मसल्स के दर्द से आराम दिलाता है।

लौंग भी नेचुरल पेन किलर

दांत में दर्द हो तो लौंग का तेल काफी काम आता है। इसके अलावा आप लौंग को दांत के नीचे रख सकते हैं। इससे भी आराम मिल जाता है। सर्दी-खांसी की वजह से गले में दर्द, सिर में दर्द हो तो लौंग की चाय पीने और लौंग चबाने से राहत मिलती है।

अजवायन दिलाएगी पेट दर्द से आराम

पेट में ऐंठन, गैस का दर्द हो रहा हो तो अजवायन को भूनकर काले नमक के साथ गुनगुने पानी से लेना चाहिए। इससे कुछ ही देर में आराम मिल जाता है। इसी तरह से हींग भी पेट की गैस से आराम दिलाने का काम करती है। बस ध्यान रखें कि अगर दस्त की समस्या है तो ये दोनों चीजें गलती से भी न लें।

पीरियड्स दर्द में अदरक

महिलाओं को हर महीने पीरियड्स के दौरान पेल्विक फ्लोर में दर्द होने के साथ ही मसल्स में होने वाली ऐंठन से भी जूझना पड़ता है। इस दौरान आप अदरक की चाय बनाकर पी सकती हैं। अदरक को उबाल लें इसे कप में छान लें और इसमें शहद मिलाकर इसे सिप-सिप कर पिएं। इससे मितली की समस्या से भी राहत मिलती है।

काली मिर्च दिलाएगी जॉइंट पेन से राहत

अगर जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है तो काली मिर्च को दूध में उबालकर लेना चाहिए। इससे शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। गले में दर्द की समस्या हो तो काली मिर्च की चाय पीने से काफी आराम मिलता है।

रसोई में रखी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो न सिर्फ पोषण देती हैं, बल्कि हेल्थ प्रॉब्लम में भी यूज की जाती हैं। ऐसी ही पांच चीजों के बारे में जानेंगे जो दर्द कम करने के काम आती हैं।

ईपीएफओ का बड़ा अपडेट, खाते में जमा पैसों पर कब तक मिलता रहेगा ब्याज?

ईपीएफ अकाउंट नौकरी छोड़ने या नौकरी बदलने के तुरंत बाद इनऑपरेटिव नहीं होता। इसलिए पुराने PF अकाउंट को नजरअंदाज करने के बजाय UAN और रोजगार रिकॉर्ड अपडेट रखना जरूरी है।

नौकरी बदलने पर PF अकाउंट तुरंत इनऑपरेटिव नहीं होता

अगर आपके पास पुराना PF अकाउंट है और उसमें पैसा जमा है, तो यह जानना जरूरी है कि उस रकम पर ब्याज कब तक मिलता रहता है। कई लोगों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही PF अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। EPFO के नियमों के मुताबिक, सिर्फ नौकरी छोड़ने या दूसरी कंपनी में नौकरी बदलने से PF अकाउंट तुरंत इनऑपरेटिव नहीं होता। कुछ खास परिस्थितियों में ही अकाउंट इनऑपरेटिव होता है और उस पर ब्याज मिलना बंद होता है।

EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए सदस्यों को इन नियमों की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि PF अकाउंट कब ब्याज कमाना बंद करता है और पुराने PF बैलेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए?

कब बंद होता है PF पर ब्याज?

EPF के नियमों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी 55 साल या उसके बाद रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के तीन साल बाद उसका PF अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है। इसके बाद उस अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति 55 साल से पहले रिटायर हो जाता है, तो उसका PF अकाउंट तुरंत इनऑपरेटिव नहीं होता। ऐसे मामले में अकाउंट 58 साल की उम्र तक ब्याज कमाता रहता है। इसके बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है।

रिटायरमेंट के बाद कब तक मिलेगा ब्याज?

मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में रिटायर होता है। ऐसी स्थिति में उसका PF अकाउंट 50 साल की उम्र में ही बंद नहीं होगा। उसे 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। इसके बाद अकाउंट इनऑपरेटिव होगा। अगर कोई व्यक्ति 55 साल में रिटायर होता है, तो उसका अकाउंट 58 साल की उम्र में इनऑपरेटिव होगा। वहीं, अगर कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो अकाउंट 61 साल की उम्र में इनऑपरेटिव होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसका PF अकाउंट 73 साल की उम्र में इनऑपरेटिव हो सकता है।

नौकरी बदलने पर क्या होगा?

नौकरी बदलने से आपका पुराना PF अकाउंट अपने आप इनऑपरेटिव नहीं हो जाता। ऐसे में अपने UAN और रोजगार से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट रखना जरूरी है। अगर आप नई नौकरी में चले गए हैं, तो पात्र होने पर पुराने PF बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर करना बेहतर होता है। जरूरत पड़ने पर नियमों के मुताबिक PF निकालने के लिए क्लेम भी किया जा सकता है। पुराने PF अकाउंट में जमा रकम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने UAN की जानकारी और नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड सही रखने से PF को मैनेज करना आसान रहता है।

36 महीने का नियम समझना जरूरी

EPFO की जानकारी का सबसे अहम हिस्सा यह है कि 36 महीने यानी तीन साल की अवधि कब शुरू होती है, इसे सही तरीके से समझना जरूरी है। खास तौर पर रिटायरमेंट की उम्र और PF अकाउंट के इनऑपरेटिव होने की तारीख को ध्यान में रखना चाहिए। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके PF बैलेंस पर ब्याज कब तक मिल सकता है। पुराने PF अकाउंट में जमा पैसा नियमों के अनुसार निकाला जा सकता है। इसलिए अगर आपका पुराना PF बैलेंस पड़ा है, तो उसे यूं ही छोड़ने के बजाय अपने अकाउंट की स्थिति जरूर जांचें।

अमेज़न पर भारी जुर्माना: राम मंदिर का प्रसाद बोलकर बेच रहे थे साधारण मिठाई, सीसीपीए ने लिया बड़ा एक्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की विक्रेता सेवा इकाई पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने यह कार्रवाई साधारण मिठाइयों को 'श्रीराम मंदिर अयोध्या प्रसाद' के नाम से बेचने और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापन दिखाने के मामले में की है।

उपभोक्ता नियामक की जांच में सामने आया कि अमेजन के मंच पर ऐसे उत्पादों की बिक्री की अनुमति दी गई, जिनके लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से कोई आधिकारिक मंजूरी या प्रामाणिकता प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अपने 19 पन्नों के आदेश में कहा कि 'श्रीराम मंदिर अयोध्या प्रसाद' शब्द देश के करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक और भावनात्मक महत्व रखता है। प्राधिकरण के अनुसार, बिना आधिकारिक अनुमति के सामान्य मिठाइयों को इस नाम से बेचकर व्यावसायिक लाभ कमाना उपभोक्ताओं को गुमराह करने के साथ-साथ उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है।

प्राधिकरण ने कहा कि अमेजन जैसे बड़े ऑनलाइन मंच की व्यापक पहुंच के कारण उपभोक्ता ऐसे विज्ञापनों को वास्तविक और प्रमाणिक मान सकते हैं। इससे भ्रामक प्रचार के प्रभाव और संभावित नुकसान में वृद्धि होती है।

यह मामला जनवरी 2024 में सामने आया था। अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ ने 19 जनवरी 2024 को अमेजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अमेजन पर चार प्रकार की मिठाइयों को अयोध्या में श्रीराम मंदिर का प्रसाद बताकर 299 से 385 रुपये के बीच बेचा जा रहा था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से तीन दिन पहले, 19 जनवरी को ही अमेजन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

जांच के दौरान सामने आया कि इन भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से कुल 25,26,309 रुपये की सकल बिक्री हुई। हालांकि, अमेजन के हिस्से में वास्तविक राजस्व 39,802 रुपये आया। इसमें से कंपनी ने सेवा शुल्क और कमीशन के रूप में 15,165 रुपये अर्जित किए।

अमेजन ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि वह केवल एक मध्यस्थ मंच है और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत उसे संरक्षण प्राप्त है। हालांकि, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं। केवल मध्यस्थ होने का दावा करके अमेजन अपनी उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्राधिकरण ने अमेजन को कई निर्देश भी दिए हैं। आदेश के अनुसार, कंपनी बिना प्रमाणिक दस्तावेज और संबंधित धार्मिक न्यास या प्रबंधन की लिखित अनुमति के देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़े किसी भी प्रसाद या भोग की बिक्री अपने मंच पर नहीं होने देगी।

इन धार्मिक स्थलों में श्रीराम जन्मभूमि, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं।

प्राधिकरण ने अमेजन को अपने मंच पर विक्रेताओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए बिना किसी लॉगिन के शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है।

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का यह आदेश ऑनलाइन खरीदारी में भ्रामक विज्ञापनों और धार्मिक आस्था से जुड़े उत्पादों की प्रमाणिकता को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।

अलास्का में घने कोहरे के बीच चार्टर्ड प्लेन क्रैश, 2 पायलटों समेत सभी 8 लोगों की मौत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के अलास्का के एक दूर-दराज के मिलिट्री एयरपोर्ट पर शुक्रवार को घने कोहरे के बीच लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कहा कि पायलट रनवे को देख नहीं पा रहे थे और उन्हें पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर रहना पड़ा, जब वे एंकरेज से लगभग 450 मील (725 किलोमीटर) पश्चिम में केप न्यूएनहैम लॉन्ग रेंज रडार साइट एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहे थे।

इस क्रैश में मारे गए दो पायलटों और छह यात्रियों की तुरंत पहचान नहीं हो पाई। मारे गए लोगों में US आर्मी कॉर्प्स ऑफ़ इंजीनियर्स के दो कर्मचारी भी शामिल थे।

लैंडिंग करते समय GPS का इस्तेमाल

यह रडार साइट 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा मिसाइल हमले की शुरुआती चेतावनी देने के लिए बनाए गए नेटवर्क के हिस्से के तौर पर बनाई गई थी। आज, यह रूस, उत्तर कोरिया और चीन की दिशा में समुद्र तट के ऊपर आसमान पर नजर रखती है। इस साइट पर पहाड़ की ढलान पर बनी बजरी वाली हवाई पट्टी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सलाह देता है कि पायलट वहां लैंडिंग करते समय GPS और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें।

लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट डेविस ने जताया दुख

अलास्कन कमांड, अलास्कन नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड रीजन और इलेवंथ एयर फोर्स के कमांडर, US एयर फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट डेविस ने एक बयान में कहा कि प्लेन में सवार लोग 'मुश्किल हालात में एक अहम मिशन को पूरा करने वाले समर्पित प्रोफेशनल थे। डेविस ने कहा कि यह हमारी मिलिट्री फैमिली और उन समुदायों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिनकी हम सेवा करते हैं।

बहुत कम हो गई थी विजिबिलिटी

गुरुवार को इलाके में घने कोहरे के कारण मौसम के हालात बदल रहे थे। नेशनल वेदर सर्विस के अलास्का सेक्टर ऑपरेशन्स सेंटर की इंचार्ज मौसम विज्ञानी कैरी हेस्ली के अनुसार, एयरपोर्ट से कुछ दूर एक ऑटोमेटेड ऑब्जर्वेशन सिस्टम ने क्रैश से कुछ मिनट पहले कम ऊंचाई वाले बादल, कोहरा और लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) की विजिबिलिटी की जानकारी दी थी, लेकिन क्रैश के लगभग 15 मिनट बाद आए अगले अपडेट में विजिबिलिटी बहुत कम होकर एक-चौथाई मील (0.40 किलोमीटर) से भी कम हो गई थी।

पैसिफिक एयर फोर्सेस रीजनल सपोर्ट सेंटर

यह एयरपोर्ट एक प्राइवेट मिलिट्री साइट है, जिसे पैसिफिक एयर फोर्सेस रीजनल सपोर्ट सेंटर मैनेज करता है। अलास्का कमांड के बयान के मुताबिक, यह दूर-दराज के रडार साइट्स के नेटवर्क का हिस्सा है जो अलास्का के एयरस्पेस और उसकी सीमाओं पर उड़ने वाले विमानों पर नजर रखता है। केप न्यूएनहैम का आउटपोस्ट 1983 में एक नया रडार लगने के बाद बंद कर दिया गया था, और अब इस साइट पर कभी-कभार ही सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर आते हैं जो सिस्टम की देखरेख करते हैं। US आर्मी कॉर्प्स ऑफ़ इंजीनियर्स ने कहा कि मारे गए दो कर्मचारी US एयर फ़ोर्स के सपोर्ट में एक प्रोजेक्ट साइट पर जा रही प्रोजेक्ट डिलीवरी टीम' का हिस्सा थे। बयान में काम के बारे में और जानकारी नहीं दी गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के जांचकर्ता शुक्रवार को घटनास्थल के लिए रवाना हुए।

क्या पायलटों ने इमरजेंसी घोषित की थी?

जांचकर्ता यह जानना चाहेंगे कि क्या पायलटों ने इमरजेंसी घोषित की थी या क्रैश से पहले ही विमान गायब हो गया था, साथ ही उस समय मौसम कैसा था। यह बात माइक ओ'डोनेल ने कही, जिन्होंने FAA में अपने 17 साल के कार्यकाल के दौरान एयरपोर्ट सेफ्टी प्रोग्राम और दुर्घटना जांच की देखरेख की थी।

कैलिफोर्निया असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली मनाने का प्रस्ताव किया पास, लोगों से की उत्सव मनाने की अपील

कैलिफोर्निया, एजेंसी। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने 8 नवंबर को 'दिवाली डे' के तौर पर मान्यता देने वाला एक प्रस्ताव पास किया और राज्य के लोगों से इस जश्न में शामिल होने की अपील की। असेंबली के सदस्यों दर्शन पटेल और ऐश कालरा द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में कैलिफोर्निया और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय-अमेरिकियों और भारतीय मूल के लोगों के प्रति गहरा सम्मान भी जताया गया है।

असेंबली द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में कहा गया, असेंबली रविवार, 8 नवंबर, 2026 को इस साल के दिवाली त्योहार को मान्यता देती है और कैलिफोर्निया के लोगों को खुशी के इस दिन के जश्न में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें कहा गया है कि दिवाली, जो भारतीय-अमेरिकियों और दक्षिण एशियाई अमेरिकियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, पूरे अमेरिका और दुनिया भर में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों द्वारा हर साल मनाई जाती है। प्रस्ताव में कहा गया है कि दिवाली या दीपावली, जिसका अर्थ है 'दीयों की कतार, दुनिया के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। यह परिवारों, दोस्तों और समुदायों को उदारता, एकता, खुशी और सराहना के जश्न के लिए एक साथ लाता है और आत्म-चिंतन का समय भी देता है। इसमें कहा गया, दिवाली, जिसे आमतौर पर 'रोशनी का त्योहार' कहा जाता है, एक ऐसा समय है जब घरों को मोमबत्तियों, तेल की लालटेन और मिट्टी के दीयों से रोशन किया जाता है और अच्छी सेहत, धन, ज्ञान, शांति और समृद्धि के प्रति सम्मान दिखाने के लिए आसमान को आतिशबाजी से भर दिया जाता है।

ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात से पहले ताइवान स्ट्रेट से गुजरा अमेरिकी विमान, चीन ने हर पल रखी नजर

ताइवान, एजेंसी। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिशों के बीच शुक्रवार को अमेरिकी नौसेना का P-8A पोसीडॉन विमान ताइवान स्ट्रेट से गुजरा। यह विमान अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में रहा। अमेरिकी नौसेना के 7वें फ्लीट ने कहा कि इस उड़ान से अमेरिका ने एक बार फिर स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।

अमेरिकी 7वें फ्लीट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ताइवान स्ट्रेट में काम करके अमेरिका सभी देशों के नौवहन अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अमेरिका का कहना है कि उसकी सेना वहां उड़ान भरती है, समुद्र में चलती है और सैन्य गतिविधियां करती है, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है। चीन की सेना ने अमेरिकी P-8A पोसीडॉन विमान की इस उड़ान को ट्रैक और मॉनिटर किया। चीन के सरकारी समर्थन वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी सेना ने पूरे ट्रांजिट के दौरान विमान पर नजर रखी और कहा कि स्थिति कंट्रोल में थी। अमेरिकी सैन्य जहाज और विमान हर कुछ महीनों में ताइवान स्ट्रेट से गुजरते हैं या इसके ऊपर से उड़ान भरते हैं। ताइवान स्ट्रेट ताइवान और चीन के बीच स्थित समुद्री रास्ता है। अमेरिका की ऐसी गतिविधियों से चीन नाराज होता है और वह लगातार इन मिशनों का विरोध करता रहा है।

ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात से पहले क्यों अहम है यह उड़ान?

इस अमेरिकी उड़ान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने अमेरिका जाने की उम्मीद है, जहां वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। वॉशिंगटन और बीजिंग इस समय अपने रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच ताइवान, व्यापार विवाद और तकनीक पर लगाए गए प्रतिबंधों जैसे कई मुद्दों को लेकर तनाव है।

ताइवान पर अमेरिका और चीन की सोच अलग

चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। बीजिंग का कहना है कि ताइवान का मुद्दा उसका आंतरिक मामला है और यह उसके सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों में शामिल है। चीन इसे ऐसी लाल रेखा मानता है, जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, ताइवान की सरकार चीन के संप्रभुता के दावे को नहीं मानती। उसका कहना है कि ताइवान के भविष्य का फैसला सिर्फ वहां के लोग कर सकते हैं।

बचपन में हुई अनाथ और अब रचा इतिहास कौन है ये महिला जिसने काबुल से अमेरिकी कांग्रेस तक का सफर किया तय

वॉशिंगटन, एजेंसी। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट आयशा वहाब को 21 अगस्त को एक बड़ी उपब्धि हासिल हुई। 39 साल की आयशा को कैलिफोर्निया के एक स्पेशल (उप) चुनाव में जीत मिली है। वो अमेरिकी कांग्रेस की पहली अफगान-अमेरिकी सदस्य बन गईं। उन्होंने अपनी ही पार्टी की मेलिसा हर्नांडेज को 53.1% वोट से हराया।

ये सीट पूर्व कांग्रेसी एरिक स्वैलवेल की थी। उन्होंने यौन दुर्व्यवहार के आरोप की वजह से अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था। आयशा जनवरी तक इस पद पर रहेंगी। आयशा को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जानते हैं उनका अब तक का सफर कैसा रहा।

आयशा का बचपन बहुत ही मुश्किलों में गुजरा है। उनका जन्म क्वींस में हुआ था। आयशा वहाब

बचपन में ही अनाथ हो गई थीं। उनके पिता की हत्या कर दी गई और उसके कुछ ही समय बाद उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें कैलिफोर्निया में बे एरिया के कपल ने गोद लिया। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। फिर MBA और सोशल वर्क में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की।

2011 में फिर बढ़ीं मुश्किलें

2011 में उन्हें फिर से मुश्किल भरे दौर से गुजरना पड़ा। उनके परिवार का घर जब्त हो गया। आर्थिक मुश्किलें बढ़ गईं। उनके माता-पिता का बिजनेस बंद हो गया। उनके गोद लिए पिता की तबीयत बिगड़ने लगी और आयशा की नौकरी चली गई। अपने समुदाय में रहने में असमर्थ होने के बाद, आयशा और उनका परिवार हेवर्ड चले गए। यहां उन्होंने काउंसिल की बैठकों में भाग लेना और किफायती आवास की वकालत करना शुरू किया।

आयशा ने 2018 में उन्होंने हेवर्ड सिटी काउंसिल की सीट जीती। उन्होंने सिटी काउंसिल में काम किया। साल 2022 में कैलिफोर्निया की स्टेट लेजिस्लेचर के लिए चुनी गईं। ऐसा करने वाली वो पहली अफगान-अमेरिकी और पहली मुस्लिम महिला बनीं।

उनकी इस बड़ी जीत के पीछे की वजह, उन्होंने खुलकर वामपंथी एजेंडे पर चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने सबके लिए मेडिकेयर, अरबपतियों पर ज्यादा टैक्स, स्टूडेंट लोन माफ करना, मजबूत सोशल प्रोग्राम और कॉर्पोरेट ताक़त को कम करने वाली नीतियां रहीं।

व्हाइट हाउस राउंडटेबल के लिए चुना गया था

आयशा बुज़ुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए एक एडवोकेट और ऑर्गनाइजर के तौर पर काम करती रहती हैं। आयशा किफायती आवास, नागरिक भागीदारी, शिक्षा और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर भी काम किया है।

आयशा पहले अलामेडा काउंटी ह्यूमन रिलेशंस कमीशन की चेयर और अफगान कोएलिशन, एबोड सर्विसेज़ और ट्राई-सिटी वॉलंटियर्स जैसे नॉन-प्रॉफिट संगठनों की बोर्ड मेंबर रह चुकी हैं। उन्होंने अलामेडा काउंटी पब्लिक हेल्थ कमिश्नर और बे एरिया विमेंस मार्च में स्पीकर के तौर पर काम किया है। फिर उन्हें व्हाइट हाउस राउंडटेबल ऑफ अफगान-अमेरिकन लीडर्स में शामिल होने के लिए चुना गया था।

विरोध करने सिंदूर लगाकर न चले आएं... बृजभूषण शरण सिंह ने रामदेव पर कसा तंज

बृजभूषण शरण सिंह, बोले-स्वदेशी के नाम पर नकली प्रोडक्स बना रहे

नई दिल्ली। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "मूल रूप से स्वदेशी के नाम पर शुरू किया गया अभियान अब नकली उत्पादों और विदेशी सामानों तक फैल गया है।" उन्होंने रामदेव को विरोध प्रदर्शन करने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर योग गुरु आंदोलन शुरू करने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें इस बार निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए और एक आदमी की तरह ऐसा करना चाहिए।

जिला मुख्यालय के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बृजभूषण ने बाबा रामदेव के आंदोलन से जुड़े सवाल पर कहा कि रामदेव ने स्वदेशी के मुद्दे को उठाना शुरू किया था, इसलिए, उनका आंदोलन उचित था। हालांकि, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रामदेव अब विदेशी अधोवस्त्र(अंडरगार्मेंट्स) भी बनाने लगे हैं। उन्होंने रामदेव के पिछले विरोध प्रदर्शनों को याद करते हुए कहा कि इस बार उनसे कहा जाना चाहिए कि वह 'सिंदूर' लगाकर और 'सलवार' पहनकर न आएं। उन्होंने दावा किया कि देश में नकली घी के प्रचलन को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। बृजभूषण ने इसके लिए रामदेव को जिम्मेदार ठहराया।

पहले भी प्रोडक्स के विरोध में दे चुके हैं बयान

24 नवंबर, 2022 को सांसद रहते हुए ही बृजभूषण ने बाराबंकी में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने अच्छी सेहत, साफ-सफाई और शुद्ध दूध व घी के सेवन करने को कहा था। उन्होंने रामदेव के प्रोडक्ट्स पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, "गाय या भैंस न पालने की वजह से लोग "रामदेव के नकली घी" का सेवन करने को मजबूर हैं।"

उस समय बीजेपी के पूर्व सांसद ने मांग की थी कि रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण अपने ब्रांड के लिए 'पतंजलि' नाम का इस्तेमाल बंद करें। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने गोंडा (जो उनका गृह जिला है) में महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली के लिए "कुछ नहीं" किया है।

2023 में रामदेव ने उन महिला पहलवानों का समर्थन किया था, जिन्होंने उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी।

स्वाइन फ्लू का बढ़ता प्रकोप : दिल्ली में 1770 से ज्यादा मामले, इन लक्षणों पर तुरंत दें ध्यान

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में इस साल अब तक स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के 1770 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, मानसून के दौरान मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर स्वाइन फ्लू की स्थिति की समीक्षा की।

सिंह ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी सरकारी अस्पतालों को इलाज की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमण के पैटर्न, प्रभावित इलाकों और संभावित हॉटस्पॉट पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड तैयार किए जा रहे हैं।

दिल्ली में एक ही दिन में एच1एन1 के 114 नए मरीज मिले। इससे इस वर्ष अब तक एन1एच1 की पुष्टि हुई मरीजों की संख्या बढ़कर 1,777 हो गई। छह अगस्त तक दिल्ली में एच1एन1 के 1,344 मामले थे। यानी मात्र 14 दिन में 433 नए मामले सामने आए। 20 अगस्त को मिले 114 नए मरीज दिल्ली के किन अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं, इसका ब्योरा स्वास्थ्य विभाग ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया है।

पिछले वर्ष इसी अवधि में 229 मामले थे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब आठ गुना मामले हो गए हैं। वहीं, एम्स के विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव और उमस के कारण इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ सकते हैं। बुजुर्गों और पहले से फेफड़े, हृदय, मधुमेह सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों में संक्रमण गंभीर होने का खतरा अधिक रहता है।

बुजुर्ग और छोटे बच्चों को ज्यादा सावधानी

सर गंगा राम अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन विभाग के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. ऋषिकेश देसाई के अनुसार, अस्पताल में मौसमी इन्फ्लूएंजा के मरीज बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि स्वस्थ लोगों में संक्रमण आमतौर पर ठीक हो जाता है, लेकिन बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में फ्लू गंभीर रूप ले सकता है। वहीं, संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा ने भी इन्फ्लूएंजा और फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीजों में बढ़ोतरी की बात कही।

सेंसर बोर्ड का फिल्म निर्माताओं के लिए बड़ा फरमान, सर्टिफिकेट के बाद कांट-छांट का मौका खत्म

सिनेमैटोग्राफ नियमों में मई 2026 में किए गए संशोधन के करीब तीन महीने बाद केंद्र सरकार ने नियम 33 में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र मिलने के बाद निर्माता अपनी फिल्म में किसी भी तरह का बदलाव, कटौती या नया दृश्य जोड़ नहीं सकेंगे।

पहले फिल्म को प्रमाणपत्र मिलने के बाद निर्माता केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सूचित कर आवश्यक मंजूरी लेकर फिल्म में कुछ बदलाव कर सकते थे। अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, संशोधित नियम 10 अगस्त 2026 से लागू हो गया है। इसके बाद प्रमाणपत्र मिलने के बाद निर्माता फिल्म की अवधि भी कम नहीं कर सकेंगे।

यदि किसी निर्माता को प्रमाणपत्र मिलने के बाद यह लगता है कि फिल्म अधिक लंबी है और उसमें से कुछ मिनट कम किए जाने चाहिए, तो अब ऐसा करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

पहले नियम 33 के प्रावधान का इस्तेमाल फिल्म में उपशीर्षक जोड़ने जैसे बदलावों के लिए भी किया जाता था। लेकिन नए संशोधन के बाद प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात ऐसे बदलाव भी नहीं किए जा सकेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, नियम 33 कागजी तौर पर मौजूद रहेगा, लेकिन प्रमाणपत्र मिलने के बाद निर्माता इसका इस्तेमाल फिल्म में बदलाव करने के लिए नहीं कर सकेंगे।

नए नियम के बाद फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के सामने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें प्रमाणन के लिए फिल्म का अंतिम संस्करण ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास प्रस्तुत करना होगा।

फिल्म की अवधि कम करने, कोई नया दृश्य जोड़ने, किसी दृश्य को हटाने या किसी अन्य तरह का फेरबदल करने का निर्णय प्रमाणन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही करना होगा।

नियम 33 में किए गए इस बदलाव से फिल्म के प्रमाणन के बाद उसमें संशोधन की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब निर्माता को प्रमाणन के लिए फिल्म भेजने से पहले ही उसकी अंतिम अवधि, दृश्यों और अन्य सामग्री को लेकर सभी निर्णय लेने होंगे।

मई 2026 में सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमों में संशोधन कर प्रमाणन की प्राथमिकता योजना को समाप्त किया गया था। अब तीन महीने बाद नियम 33 में हुए इस बदलाव को फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रिया चक्रवर्ती बोलीं– देश में सबसे ज्यादा ट्रोलिंग मैंने सही है, दुनिया मुझे गद्दार मानती है

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती इन दिनों रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आ रही हैं। वर्ष 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया था। मामले की जांच के दौरान रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। बाद में मामले में रिया के खिलाफ आरोपों को लेकर उन्हें राहत मिली। अब शो के पांचवें एपिसोड में रिया ने बताया कि वह 'गद्दार' की भूमिका क्यों नहीं निभाना चाहतीं।

शो में श्वेता तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए रिया ने कहा कि वह गद्दार नहीं बनना चाहतीं, क्योंकि दुनिया पहले ही उन्हें गद्दार मान चुकी है। उन्होंने कहा कि यह बात उनके निजी जीवन के अनुभवों से जुड़ी है।

रिया के अनुसार, वह किसी मनोरंजन कार्यक्रम में आकर अपनी इच्छा से किसी की 'हत्या' जैसी भूमिका नहीं निभाना चाहतीं, क्योंकि इससे उनके खिलाफ फिर से नकारात्मक प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोग इस पर भी आपत्तिजनक मजाक और मीम बना सकते हैं।

रिया ने खुद को देश में सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाने वाली हस्तियों में से एक बताते हुए कहा कि वह फिर से उसी तरह के दौर से नहीं गुजरना चाहतीं।

रिया ने शो के अन्य प्रतिभागियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वह गद्दार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही है कि लोगों ने उन्हें गद्दार समझा, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष बताया गया।

उनका यह बयान सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और उसके बाद हुई जांच की ओर इशारा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बाद में मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके बाद रिया को बड़ी राहत मिली।

शो की शुरुआत में मेजबान करण जौहर ने रिया से पूछा था कि वह कार्यक्रम में बेकसूर की भूमिका निभाना चाहती हैं या गद्दार की।

इसके जवाब में रिया ने कहा था कि वह बेकसूर बनना चाहती हैं।

रिया ने कहा था कि वर्षों तक उन पर संदेह किया गया, जो उनके लिए बेहद कठिन अनुभव था। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्हें जांच से राहत मिली और लोगों को उनके पक्ष की जानकारी मिली। इसलिए वह दोबारा उस दौर से नहीं गुजरना चाहतीं।

वर्ष 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती को जांच और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और सार्वजनिक स्तर पर भी उन्हें भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी।

बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच में उन्हें राहत मिली। रिया ने अपने पिछले साक्षात्कारों में बताया था कि इस पूरे घटनाक्रम का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह भी कहा था कि इस कठिन दौर के कारण उन्हें गंभीर मानसिक दबाव से गुजरना पड़ा।

फिलहाल रिया 'द ट्रेटर्स 2' में प्रतियोगी के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही हैं और कार्यक्रम में उनके पुराने जीवन से जुड़े अनुभव लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं।

4 किरदार, एक अनोखी वाइब और कई सवाल, कुणाल खेमू की फिल्म का नया पोस्टर जारी, आएगा टीजर

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने अपनी अपकमिंग फिल्म वाइब का पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर कुणाल खेमू की इस हाई-स्टेक्स एक्शन कॉमेडी की एक और झलक दिखाता है और साथ ही कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिर इस अनोखी चौकड़ी के साथ क्या होने वाला है। साथ ही बताया है कि फिल्म वाइब का टीजर किस दिन रिलीज होगा।

नए पोस्टर की बात करें तो इसमें प्रीति जिंटा एक दमदार बॉस-लेडी अवतार में नजर आ रही हैं। वहीं इसके बिल्कुल उलट कुणाल खेमू, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इससे इशारा मिल रहा है कि आखिर वे जिस मुसीबत में फंसे हैं, वह पूरी तरह से उनके हाथ से निकल चुकी है।

वाइब की कहानी दो ऐसे जिगरी दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी सीधी-सादी जिंदगी अचानक एक अनजान और हाई-एनर्जी एडवेंचर में बदल जाती है। यह सफर उनकी जान बचाने की काबिलियत और उनकी दोस्ती, दोनों की कड़ी परीक्षा लेता है।

कुणाल खेमू ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है। वाइब को कुणाल खेमू और चिराग निहलानी ने ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में कुणाल खेमू के साथ प्रीति जी जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और डेब्यू कर रहीं वंशिका धीर लीड रोल में हैं। कल यानी 21 अगस्त को टीजर रिलीज होगा और इसके साथ ही फिल्म दर्शकों को एक हाई-एनर्जी एडवेंचर पर ले जाने के लिए तैयार है।अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की फिल्म वाइब 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बता दें, ड्रोंगो फिल्म्स एक प्रोडक्शन बैनर है, जिसे एक्टर-डायरेक्टर-राइटर कुणाल खेमू और प्रोड्यूसर चिराग निहलानी ने मिलकर शुरू किया है। यह दोनों की ईमानदार और दिलचस्प कहानियां पेश करने के जुनून से बना है। क्रिएटिविटी के साथ-साथ मजबूत और साफ तरीके से काम करने पर फोकस करते हुए ड्रोंगो फिल्म्स ऐसी नई और दिल को छू लेने वाली कहानियों को पर्दे पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ें। अब फिल्म वाइब का दर्शकों पर कितना असर पड़ेगा, यह तो 18 सितंबर को ही पता चलेगा।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित । शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website : aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com